**Sixteenth Loksabha**

an>

Title: Discussion on the Supplementary Demands in respect of Budget for 2018-19 (Discussion concluded).

HON. SPEAKER: Now, the House shall take up Item No. 21 - Discussion on Supplementary Demands for Grants - Second Batch for 2018-19.

…(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Motion moved:

> "That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2019, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 5, 8, 9, 11, 13 to 18, 20, 23 to 36, 41, 42, 44, 46 to 48, 52 to 54, 56 to 61, 64 to 68, 70, 72 to 74, 78, 80 to 82, 84 and 87 to 99."

**DEMANDS**

HON. SPEAKER: Nishikant Dubey Ji.

…(*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** निशिकान्त जी, अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आप बोलिए।

…(व्यवधान)

**श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** अध्यक्ष महोदया, आपका धन्यवाद। …(व्यवधान) खड़गे साहब, किसी चीज पर चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** आप डिस्कशन करिए।

…(व्यवधान)

**श्री निशिकान्त दुबे :** अध्यक्ष महोदया, जे.पी.सी. में, बोफोर्स में तो इनको क्लीन चिट मिल गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, इनकम टैक्स का रूलिंग आ गई कि बोफोर्स में चोरी हुई है। जे.पी.सी. में तो इनको क्लीन चिट मिल गई थी। उसी तरह जे.पी.सी. इन्होंने 2जी पर बना दी। उसका क्या फायदा हुआ? ये केवल पाइंट स्कोर करने के लिए, जे.पी.सी. जब सरकारी पार्टी है, उसमें सरकार का अध्यक्ष होता है, तो फिर रिपोर्ट कैसे आती है? …(व्यवधान) चेयरमैन तो मुझे पार्टी बनाएगी। खड़गे साहब, चेयरमन मुझे कांग्रेस नहीं बनाएगी। …(व्यवधान) चेयरमैन तो पार्टी बनाएगी।

**माननीय अध्यक्ष :** आज सुबह होम मिनिस्टर जी ने साफ-साफ बोला है कि वे डिस्कशन के लिए तैयार हैं। तो दोबारा हर मिनिस्टर कुछ नहीं बोलेगा। बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** डिस्कशन कीजिए।

…(व्यवधान)

**श्री निशिकान्त दुबे :** माननीय अध्यक्ष महोदया, …(व्यवधान) मैं सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स फार ग्रान्ट्स के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। …(व्यवधान)

**14 07 hrs**

*At this stage, Shri Rajeev Satav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

**माननीय अध्यक्ष :** आप सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स फार ग्रान्ट्स पर बोलिए।

…(व्यवधान)

**श्री निशिकान्त दुबे :** अध्यक्ष महोदया, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब वर्ष 2014 से हमारी सरकार बनी है, सबका साथ सबका विकास हो, …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** एक मिनट प्लीज।

…(व्यवधान)

**वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) :** मेरा सुझाव है कि राफेल पर तुरंत चर्चा शुरू करवा दी जाए। खड़गे साहब शुरू करें और मैं जवाब देता हूं। अगर हमने यह साबित न कर दिया कि इनकी पार्टी ने सौ 'झूठ' बोले हैं, तो उसके बाद जो ये कहेंगे हम मान जाएंगे। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** क्या आप चर्चा चाहते हैं, do you want a discussion?

… (*Interruptions*)

**14 08 hrs**

*At this stage, Shrimati V. Sathyabama and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

**श्री निशिकान्त दुबे :** अध्यक्ष महोदया, इसमें जो सबसे पहला है, …(व्यवधान) मैंने कितनी बार कहा है कि जे.पी.सी. का कोई मतलब नहीं होता है। सरकारी पार्टी का अध्यक्ष होता है, सुप्रीम कोर्ट और जे.पी.सी. के बाद, मैं आपको बता रहा हूं कि बोफोर्स में, 2जी में, जे.पी.सी. की पूरी रूलिंग के बावजूद में इन लोगों का करप्शन पकड़ा गया है और अभी जो अगस्ता वेस्टलैंड का मामला चल रहा है, उसमें मिसेज 'जी' का नाम आ रहा है, ये कांग्रेस के लिए डूब मरने वाली बात है। …(व्यवधान) इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि पहले अपना फैसला कर लीजिए।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** आप बगैर तैयारी के आते हैं। …(व्यवधान)

**श्री निशिकान्त दुबे :** जब राफेल का मुद्दा आप इतने दिनों से उठा रहे हैं, तो बगैर तैयारी का कौन सा मुद्दा है? …(व्यवधान) जिस दिन से यह पार्लियामेंट चालू हुई है, 11 तारीख से राफेल की बात कर रहे हैं और अभी तक इनकी तैयारी नहीं है। यदि तैयारी नहीं है, तो यह जनता और पूरे देश को बताने वाली बात है कि कांग्रेस केवल ऐसे ही पार्लियामेंट बंद करना चाहती है। उसको किसी डिस्कशन से कोई मतलब नहीं है और वह किसी चर्चा में भाग नहीं लेना चाहती है। यदि चर्चा में पार्ट लेना चाहती है, तो तैयार रहे। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

**श्री निशिकान्त दुबे :** अध्यक्ष महोदया, ये जो सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स ऑफ ग्रान्ट्स इसमें हमने equity infusion into Air India under the Turnaround Plan के तहत 2,345 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है। अब आप समझिए कि ये 2,345 करोड़ रुपये भारत सरकार को देने की क्यों आवश्यकता पड़ी। जब हमारी सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार थी, आपको आश्चर्य होगा कि एयर इंडिया भी प्राफिट में चल रही थी और इंडियन एयरलाइन्स भी प्राफिट में चल रही थी।…(व्यवधान) एक फाइन मार्निंग ये लोग जागे और इन लोगों ने यह तय किया कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स इन दोनों का मर्जर कर देना है। उस मर्जर के बाद किस तरह से इन्होंने एयरक्राफ्ट खरीदे, किस तरह से इनकी पालिसी हुई, किस तरह से मैनेजमेंट हुआ, उसका यह नतीजा निकला कि दिन-प्रतिदिन एयर इंडिया घाटे में जाने लगी। घाटे में जाने के कारण, आज ऐसी परिस्थिति हो गई, जब

हमारी सरकार वर्ष 2014 में बनी, टर्न इन आन प्लान जो इन्होंने लगाया था, उसमें आपको आश्चर्य होगा कि पचीस हजार करोड़ रुपये इन्होंने ड्रेन में डाल दिया। इनके पास कोई पालिसी नहीं थी कि यदि हम हजार करोड़ रुपये देंगे तो उसका क्या मतलब है। यदि दो हजार करोड़ रुपये देंगे तो, उसका क्या मतलब होगा। एयरक्राफ्ट की लीजिंग होगी, तो उसका क्या मतलब होगा। बाइलेट्रल होगा, तो क्या मतलब होगा।

मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा वाली हालत थी कि नवाब वाजिद अली शाह का जमाना था और लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। जिस तरह से इन्होंने चाहा, उस तरह से करप्शन के आधार पर ये डिसीजन ले लिया। हम लोगों के ऊपर एयर इंडिया का पचास-साठ हजार करोड़ रुपये का एक बड़ा नुकसान हमारे माथे पर मंढ़ दिया कि हम उसको कैसे चलाएं। जब से हमारी सरकार बनी है, पहली बार ऐसा हुआ है कि एयर इंडिया का जो आपरेटिंग प्राफिट है, वह हमारे पक्ष में आया है। यदि आपरेटिंग प्राफिट हमारे पक्ष में आया है, तो हम यह प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से उसके सारे घाटे को पार करते हुए, किस तरह से प्रोफेशनल्स को लाते हुए, आज ही माननीय सुरेश प्रभु जी का एक बयान है कि अगर जरूरत होगी तो हम विदेशों से भी प्रोफेशनल्स को लाएंगे। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल है, उसमें इक्विटी इन्फ्यूज करना, जिसके लिए सप्लीमेन्ट्री डिमांड फार ग्रान्ट्स में एक बहुत बड़ा प्रोविजन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी, जब वाजपेयी जी की सरकार गई, माननीय स्पीकर महोदया, उस समय मंत्री आप भी रही थीं, उस समय पहला  इकोनामिक सर्वे जो इन्होंने वर्ष 2004 में दिया था, तो वर्ष 2004 के इकोनामिक सर्वे में यूपीए सरकार ने कहा कि इतनी रोबस्ट इकोनामी ये सरकार छोड़कर गई है, जिसके आधार पर हम कोई भी फ्यूचर का विकास नहीं कर सकते हैं। धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि 7 प्रतिशत का ग्रोथ, 8 प्रतिशत का ग्रोथ और 9 प्रतिशत का ग्रोथ होता रहा। लेकिन इन्होंने फिस्कल मैनेजमेंट जो एफ.आर.बी.एम. एक्ट हम लोगों ने वर्ष 2003 में पास किया था, जिसके आधार पर फिस्कल डेफिसिट किसी भी तरीके से 3 प्रतिशत से नीचे लाना था, इन्होंने वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2009 तक ऐसी परिस्थिति पैदा की कि वह जो जी.डी.पी. का फिस्कल डेफिसिट है, वह 4 प्रतिशत पर चला गया था। उसी के आधार पर धीरे-धीरे वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक की परिस्थिति ऐसी रही कि वह 4.5 से लेकर 6.5 प्रतिशत हो गया। इसके बाद जब इन्होंने 200 डिस्ट्रिक्ट में, जो सो काल्ड मनरेगा कानून है, उसे लागू किया। मैं आज भी मानता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो बाते कही हैं और राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार लगातार पैसा देती रही है। गरीबों को पैसा जाना चाहिए, गरीबों को सब्सिडी जानी चाहिए। उसके लिए पूरे देश भर में मनरेगा लागू है। उसके आधार पर केन्द्र सरकार पचास हजार करोड़ रुपये से लेकर सत्तर हजार करोड़ रुपये तक प्रत्येक वर्ष खर्च करती है। लेकिन मैं आपको आज बताता हूं कि यदि करप्शन की जननी का कोई कार्यक्रम है, तो वह मनरेगा है। कोई ऐसा माननीय सदस्य यहां दिल पर हाथ रखकर बोले कि उसमें 50 प्रतिशत से लेकर 55 प्रतिशत तक का कमीशन नहीं है। उसके कारण जो फिस्कल मैनेजमेंट था, वह भारत सरकार का गड़बड़ा गया था। आप समझिए कि फिस्कल

डेफिसिट 6 प्रतिशत से ज्यादा जी.डी.पी. नुकसान में चली गई, जिसके कारण भारत सरकार को अपनी इकोनामी को ठीक करना काफी महंगा पड़ गया था।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे डिमांड फार ग्रान्ट्स में इन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को जो पैसा दिया है, ये इन्होंने दिया है कि subsidy to State Government on decentralized procurement of food grains under National Food Security Act (NFSA). इसके लिए लगभग 850 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इस देश में कोई भी गरीब भूखा नहीं हो, सबका साथ, सबका विकास हो। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ है, उस एक्ट में हम 70 प्रतिशत लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। 70 प्रतिशत लोगों को जब बेनिफिट दे रहे हैं, उसके लिए लगातार व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इसमें जो ये डिमांड फार ग्रान्ट्स आ रहा है, उसमें आधार के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना बड़ा करप्शन था। बायोमैट्रिक लागू होने के बाद, आधार लागू होने के बाद हमने लगभग 60 हजार करोड़ रुपये से लेकर 70 हजार करोड़ रुपये इस देश के हित में बचाया है। इतना बड़ा करप्शन किसकी जेब में जा रहा था, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। उसके आधार पर हमने इसके लिए एक प्रोविजन किया हुआ है। हमने अपनी सरकार आने के बाद एक जो पालिसी पैरालिसेस थी। पालिसी पैरालिसेस क्या था कि रेक्ट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का एक जमाना था। अभी-भी कई एक डिस्प्यूट ऐसे हैं, जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। बाहर के लोग यह चिंता करते थे कि यदि हम जाएंगे तो भारत सरकार कोई भी कानून किस तरह से चेंज करेगी। इस सरकार ने आने के बाद और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस डिमांड फार ग्रान्ट्स में हमने इनकम टैक्स के लिए, डायरेक्ट टैक्स के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, कई एक लेज़िस्लेचन के लिए, कई एक आफिसर्स के लिए पैसों की व्यवस्था की है।

इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले पॉलिसी पैरालिसिस खत्म किया।...(व्यवधान) करप्शन तो खत्म किया ही, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इस करप्शन में मैंने जैसे आपको बताया कि बायोमैट्रिक लागू नहीं था, 70 हजार करोड़ रुपया था।...(व्यवधान) एक पूरा का पूरा ज़माना है, मैं आपको बताऊँ कि वर्ष 1948 से लेकर 2014 तक की बात करेंगे तो किस करप्शन की याद करें।...(व्यवधान) वर्ष 1948 में चुनाव होने के पहले ही जीप घोटाला हो गया, साइकिल घोटाला हो गया, मुंगरा कांड हो गया, बोफोर्स हो गया। उसी तरह से आप यह समझें कि यह अगस्ता वेस्टलैंड में, अभी पूरा देश जिस तरह से सोच रहा है कि किसके आधार पर किसके पास पैसा गया।...(व्यवधान) इस कारण से यह रेट्रोस्पेक्टिव टेक्सेशन जो है, केवल लोगों को दबाने के लिए है। केवल फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट को रोकने के लिए और इसके आधार पर हम एक नई नीति लेकर आए हैं।...(व्यवधान) उसी तरह से मैं आपको बताऊँ कि हमने पैसा जो दिया है, फॉर वर्क रिलेटिंग टू एनआरसी, असम में सुप्रीम कोर्ट के

डायरेक्शन के आधार पर। आज ही आपने ज़ीरो अवर में मुद्दा उठाने को दिया। पूरे 30, 35, 40 साल से पूरा देश इस चीज़ से परेशान है कि बंग्लादेश के लोग यहाँ आकर नागरिक बन रहे हैं।...(व्यवधान) यहाँ सतपाल सिंह जी बैठे हुए हैं मुम्बई के पुलिस कमिश्नर थे, इसके लिए ये पूरे परेशान रहे। उसी तरह मैं आपको बताऊँ कि हिमाचल प्रदेश में अनुराग सिंह ठाकुर साहब के शिमला में उसी तरह की समस्या है।...(व्यवधान) मुम्बई की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, मैं जहाँ संथाल परगना से आता हूँ, चाहे वह बिहार का सवाल हो, बंगाल का सवाल हो, चाहे असम का सवाल हो और इस कारण से एनआरसी लागू करना, वह सबसे बड़ा विषय है।...(व्यवधान) केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस केवल बंग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बसाती रही, यहाँ नागरिक बनाती रही, यहाँ के लोगों को वोटर बनाती रही और कैसे जीता जाए, इस कारण से मुस्लिम अपीज़मेंट करती रही।...(व्यवधान) हमारी सरकार जब से आई है आधार कार्ड लागू होने के बाद हमने यह तय किया है कि अभी हमने असम के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपया दिया है। एक जमाना ऐसा आएगा कि पूरे देश भर में हम एनआरसी लागू करेंगे।...(व्यवधान) जो भी बंग्लादेशी घुसपैठिये हैं, उनको वोट बैंक की राजनीति का पार्ट नहीं होने देंगे। जो यहाँ के नागरिक हैं, वही वोटर बनेंगे, वही सरकार को चुनेंगे।...(व्यवधान) आपकी राजनीति को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। इस कारण से हमने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में एनआरसी के लिए पैसा दिया है।...(व्यवधान)

इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर के लिए हमने पैसा दिया है।...(व्यवधान) उसका कारण आप यह समझे कि जब 1950-51 में सरकार बनी, तब एक एम्स था। जब अटल जी की सरकार बनी, वे छ: एम्स लाए।...(व्यवधान) जब प्रधान मंत्री 2014 में आए, तब उन्होंने कहा कि कोई ऐसा राज्य नहीं बचेगा जहाँ कि हम एम्स नहीं दे देंगे। मेरे देवघर को भी एक एम्स मिला है।...(व्यवधान) हमारे जैसे जो पिछड़े इलाके के लोग हैं, जिनके पास दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, उस पैसे को वह कैसे लाएँगे, कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे इलाज कराएँगे, कैसे दिल्ली में रहेंगे, कैसे मुम्बई में रहेंगे और उस कारण से माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के प्रत्येक राज्य में एम्स देने का फैसला किया है।...(व्यवधान) उसके लिए सीजीएचएस की फैसिलिटी कैसे होगी, डॉक्टर्स की फैसिलिटी कैसे होगी, एनआरआई चेन कैसे आगे बढ़ेगा? उसमें से हम यह सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स लेकर आए हैं।...(व्यवधान)

इसके बाद रोज़गार की बात है। कई लोग कहते हैं कि यह जो डेवलपमेंट हो रहा है, यह विदाउट एम्प्लॉयमेंट हो रहा है।...(व्यवधान) इसमें पूरा ग्लोबल वर्ल्ड होने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल आया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने टूजी, कॉलगेट, सीडब्ल्यूजी, आईपीएल इस तरह के घोटाले को देखा, उन घोटालों के बाद पूरे देश के सारे बिजनेसमैन की और विदेश के सारे बिजनेसमैन की पूरी स्थिति ऐसी हो गई कि भारत एक ऐसी जगह है, जहाँ इनवेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं।...(व्यवधान) अभी आप देखें कि किस तरह से

अगस्ता वेस्टलैंड में खरीद हुई और किस तरह से ये लोग फँसे हुए हैं। लोगों को लगता था कि बिना पैसे खिलाए हुए, बिना पैसे दिए हुए आप नहीं कर सकते हैं।...(व्यवधान) इस भारत सरकार ने जिस तरह से अपने नियम को बदला है और मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को और खासकर माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहाँ हम 130 नम्बर पर थे, आज हम लोग 50 नम्बर पर पहुंच गए हैं।...(व्यवधान) यदि यह सिचुएशन इसी तरह से आगे हुई तो हम दुनिया में 10 नम्बर पर पहुँच जाएँगे।...(व्यवधान)

उसके बाद एफडीआई लिबरलाइजेशन- चाहे वह पावर सेक्टर हो, चाहे वह टेलिकॉम सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, चाहे मेन्यूफेक्चरिंग सेक्टर हो, एक समय ऐसा था कि हम मोबाइल इक्विपमेंट के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं, हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं।...(व्यवधान) सब चाइना के ऊपर निर्भर था, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने, माननीय प्रधान मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने एफडीआई को लिबरलाइज किया है, उसके कारण आप समझिये कि 200 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कम्पनियाँ यहाँ काम कर रही हैं और लोगों को हम रोज़गार देने की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था।...(व्यवधान) जीएसटी इस देश का सबसे फार रीचिंग है।...(व्यवधान) इस सरकार की दो चीजें ऐसी हैं, जिनके बारे में बहुत क्रिटिसिज्म होता है।...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी ऐसे फार रीचिंग थे, जिन्हें माननीय प्रधान मंत्री जी ही कर सकते थे।...(व्यवधान) माननीय मोदी जी के अलावा इस देश में किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं थी कि इतने बड़े रिफार्म को लागू कर दें।...(व्यवधान) डीमोनेटाइजेशन के बाद, आज जो छोटे-छोटे लेबर हैं, जो पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, जो रियल एस्टेट सैक्टर में काम करते हैं, जो ठेले वाले हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, जो दुकान में काम करते हैं, इन सभी को डिजिटल पेमेंट होना शुरू हो गया, उनका पीएफ कटना शुरू हो गया, उनको पेंशन मिलनी शुरू हो गई।...(व्यवधान) इस डिजिटल इकोनामी के कारण, लोगों को लगता है कि जितना पैसा बाहर था, उतना पैसा जमा हो गया।...(व्यवधान) एग्रीड, जितना पैसा था, उतना पैसा जमा हो गया, लेकिन जो अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में पैसे थे, जो पैसे ब्लैक मनी में थे, वे सब पैसे अंदर आ गए हैं।...(व्यवधान) अब हमने जो नोटिस देना शुरू किया है, उसके आधार पर इकोनामी को स्ट्रीमलाइन करने में मदद मिलेगी, इससे नक्सलवाद कम हो गया।...(व्यवधान) यदि जम्मू-कश्मीर की बात करें, तो जिस तरह से लोग वहाँ अटैक कर रहे थे, उसमें कमी आ गई।...(व्यवधान)

मैं नक्सलवादी क्षेत्र से आता हूं। मैं और कड़िया मुंडा जी, विद्युत वरण महतो साहब यहां बैठे हुए हैं, एक जमाना था कि खूंटी, लोहरदगा, पलामू, चतरा आदि जिले, सारण्डा और सरयू के जो फॉरेस्ट थे, हमारा जो संथाल

परगना था, वह पूरा का पूरा और छत्तीसगढ़, ओडिशा में हमेशा रोज लड़ाई होती थी।...(व्यवधान) आज नक्सलवाद में कमी आ गई है।...(व्यवधान) डीमोनेटाइजेशन के कारण यह फायदा हुआ।...(व्यवधान)

इसी तरह से जीएसटी के कारण फायदा हुआ।...(व्यवधान) आप समझिए कि पहले कई ऐसे सैक्टर थे, जिनका टैक्स ही नहीं आता था, उनका अता-पता ही नहीं था, चाहे वह टैक्सटाइल सैक्टर हो, चाहे छोटे-छोटे इण्डस्ट्री में लोग हों।...(व्यवधान) आज आप देखिए कि जीएसटी के कारण पूरा का पूरा ऐसा सिस्टम आ गया, जिसमें एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर प्रत्येक महीने इसका रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है।...(व्यवधान) इस लेजिस्लेशन के लिए और जिस तरह से जीएसटी में संशोधन पर संशोधन हो रहे हैं और जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि 12 से 15 परसेंट टैक्सेशन हो जाएगा।...(व्यवधान) लोगों को सस्ता सामान मिलेगा।...(व्यवधान) टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स और उसके बाद टैक्स की जो चोरी थी, यह रुक जायेगी।...(व्यवधान) इसके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है।...(व्यवधान)

इसके बाद मैं पेट्रोलियम सब्सिडी की बात करना चाहता हूँ।...(व्यवधान) मैं आपको बताता हूँ, मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक इस लोक सभा का कोई ऐसा सत्र नहीं रहा, जब हमने पेट्रोल प्राइस के हाइक के लिए इस सदन में चर्चा नहीं की।...(व्यवधान) हमने सिर्फ सदन में चर्चा ही नहीं की, बल्कि कई एक बार हम लोगों ने सरकार को सेंसर करने का प्रयास भी किया।...(व्यवधान) स्पीकर महोदया, आप खुद उस लोक सभा की सदस्य रही हैं और हम लोगों के साथ आप लड़ाई लड़ती रही हैं।...(व्यवधान) इस सरकार के आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने पेट्रोलियम प्राइस के रेट को कम किया है और इतना ही नहीं किया, हमने उसका एक रिजर्व पूल बनाने का प्रयास किया।...(व्यवधान) इससे 6 महीने से लेकर साल भर तक हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।...(व्यवधान) यही कारण है कि उज्ज्वला जैसी स्कीम, जो हमने लांग टर्म पॉलिसी के आधार पर, जो गैस सिलेंडर अमीरों का माना जाता था कि अमीर ही उसका यूज करेंगे, आज वह सिलेंडर सभी लोगों को मिलेगा।...(व्यवधान) पहले एस.सी.-एस.टी. और ओबीसी को दे दिया, आज हमने ऐसा किया, माननीय प्रधान मंत्री जी ने उस उज्ज्वला स्कीम में ऐसा किया कि जो भी गरीब है, चाहे वह फारवर्ड है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे एस.सी. है, चाहे एस.टी. है, कोई किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग, सम्प्रदाय का हो, वह सभी को मिलेगा।...(व्यवधान) रिडेक्शन ऑफ पेट्रोलियम सब्सिडी, जो पिछले 3.5-4 साल से भारत सरकार ने की है, उसके आधार पर यह हुआ है।...(व्यवधान) इसके बाद कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर मैं बताना चाहूँगा।...(व्यवधान) इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कई एक ऐसे हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज को हमने 2,784 करोड़ रुपए दिए हैं।...(व्यवधान) होता यह था कि जैसे हम लोग गरीब इलाके से आते हैं, वहाँ पीडब्ल्यूडी की रोड नहीं है, जो पीएमजीएसवाई की रोड बनती थी, वह खदान के कारण टूट जाती थी, क्योंकि वह 5-7 टन से

ज्यादा भार लेने की स्थिति में नहीं थी।...(व्यवधान) सेन्ट्रल रोड फंड के माध्यम से या इक्विटी के माध्यम से या बीओटी के माध्यम से आप समझें कि भारत सरकार ने यह फैसला किया है और सबसे ज्यादा काम यदि कहीं हुआ है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे में हुआ है और भारत सरकार उसकी लगातार मदद कर रही है।...(व्यवधान) अब ऐसा हो गया है कि नक्सलवादी एरिया में पीएमजीएसवाई-टू के तहत या सीआरएफ के तहत उसी तरह से 15-20 टन के भार का रोड बन रहा है।...(व्यवधान) चार-चार लेन के रोड बन रहे हैं।...(व्यवधान) उस कारण से राज्य सरकार को भी उसका फायदा हो रहा है।...(व्यवधान) राज्य सरकार के पास उतने संसाधन नहीं थे कि वह रोड बना पाये।...(व्यवधान)

राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वे उसे पी.डब्ल्यू.डी. में कन्वर्ट कर पाएं।...(व्यवधान) मैं ही आपको बताऊं कि छः-सात नेशनल हाईवेज तो हमारे लोक सभा संसदीय क्षेत्र गोड्डा को ही मिले हैं।...(व्यवधान) इतना बड़ा काम इस सरकार ने किया है और भारत सरकार ने उसमें पैसे देने का काम किया है।...(व्यवधान) उसी तरह से, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन के लिए हमने पैसे देने का काम किया है।...(व्यवधान) उस दिन किरेन रिजीजू जी बोल रहे थे कि नॉर्थ-ईस्ट में कौन-कौन से राज्य हैं, लोगों को आज यह पता चल रहा है।...(व्यवधान)

दूसरों की बात छोड़िए, मैं आपको बताऊं कि हमारे संथाल परगना में एक टेलिफोन नहीं लगता था।...(व्यवधान) वहां टेलिफोन के टावर्स नहीं थे।...(व्यवधान) नॉर्थ-ईस्ट की तो बात छोड़िए।...(व्यवधान) पहली बार इस सरकार ने वर्ष 2014-15 के बाद यह फैसला किया कि सभी जगह टेलिफोन के टावर्स लगेंगे, ब्रॉडबैन्ड लगेंगे।...(व्यवधान) आज सारे पंचायतों में ब्रॉडबैन्ड लगने की स्थिति में हैं, कई एक चालू भी हो गए हैं।...(व्यवधान) उसी तरह से, नॉर्थ-ईस्ट में टेलिफोन के टावर्स लग रहे हैं।...(व्यवधान) वहां कनेक्टिविटी बढ़ रही है।...(व्यवधान) नक्सली क्षेत्रों में लगभग दो हजार, सवा दो हजार टावर्स लगे हैं।...(व्यवधान) अगले फेज में तीन हजार टावर्स और लगने की बात चल रही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मेरा यह कहना है कि यह सरकार बी.ई., आर.ई. और पी.ई. के आधार पर नहीं चलती है, बल्कि यह सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के आधार पर चलती है।...(व्यवधान) यह सरकार भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए चलती है।...(व्यवधान) यह सरकार गांव, गरीब, किसानों को कैसे फायदा होगा, उस आधार पर चलती है।...(व्यवधान) महिलाओं का कैसे विकास होगा, यह सरकार इस पर चलती है।...(व्यवधान) हमारा जो चौकीदार है, सारे चोर किस तरह से रात में सो नहीं पाएं, यह सरकार उसके आधार पर चलती है।...(व्यवधान) ये जो चोर हैं, ये हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं।...(व्यवधान) 'उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे' - यह स्थिति यह काँग्रेस लागू करने वाली है।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से काँग्रेस के मित्रों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आपमें हिम्मत है, हैसियत है, यदि आपमें ताकत है, यदि आपके पास मुद्दे हैं तो आप राफेल के मुद्दे पर बात करें।…(व्यवधान) बात करने के बाद यदि आपको लगता है कि आप प्रभावी हो सकते हैं तो हमारी सरकार आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने को तैयार है।…(व्यवधान) सदन में यह चर्चा का विषय है और यह बहुत अच्छी बात है कि बजट के पहले सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर चर्चा होनी चाहिए, देश की चर्चा होनी चाहिए।…(व्यवधान) सड़क से संसद के आधार पर किसानों की बात होनी चाहिए, नॉर्थ-ईस्ट की बात होनी चाहिए।…(व्यवधान) गरीबों की बात होनी चाहिए, महिलाओं की बात होनी चाहिए, लेकिन आप लोग तख्ती लिए हुए हैं।…(व्यवधान)

महोदया, मैं पुन: इस सरकार को धन्यवाद देते हुए पूरे सदन को यह कहना चाहता हूं कि यह एक अच्छा सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है।…(व्यवधान) सरकार ने अपने हिसाब से एक फ्यूचर कोर्स-ऑफ-एक्शन तय किया है।…(व्यवधान)

महोदया, अन्त में, मैं सरकार से केवल एक बात कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे, कि आपने दो साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कही थी।…(व्यवधान) इस देश में दस करोड़ लोग गरीब हैं।…(व्यवधान) मेरा सुझाव है कि जब आप अगली बार वोट-ऑन-एकाउंट लेने जाएंगे तो यह जो मनरेगा है, यह करप्शन का एक बहुत बड़ा अड्डा है।…(व्यवधान) इसमें 50 से 60 प्रतिशत करप्शन है।…(व्यवधान) हमें गरीबों को पैसा देना है, इसके आधार पर यह नियम लागू हुआ है।…(व्यवधान) आप फुड सब्सिडी में पैसे दे रहे हैं, आप वृद्धावस्था पेंशन में पैसे दे रहे हैं, आप विधवा पेंशन में पैसे दे रहे हैं।…(व्यवधान) कुल मिलाकर आप तीन लाख, साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये प्रत्येक साल सब्सिडी के आधार पर देते हैं।…(व्यवधान) मेरा आपसे आग्रह है कि इन दस करोड़ गरीब परिवारों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम चालू कीजिए।…(व्यवधान) यदि उनके एकाउंट में कम से कम तीन हजार रुपये प्रति माह चले जाएंगे तो गांव की गरीबी खत्म हो जाएगी, लोगों का कल्याण हो जाएगा और हमारी सरकार ने जो एक वायदा किया था कि कोई बी.पी.एल. नहीं रहेगा, सभी अमीर रहेंगे, उसके आधार पर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे।…(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।…(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I stand here to participate in the discussion on Second batch of Supplementary Demands for Grants for 2018-19, which have sought to authorise gross additional expenditure of around Rs.80,948 crore.

Madam, I was going through the details of the Supplementary Grants which have very rightly allocated some funds related to infusion of equity in Air India to make a turn around.

It has also made provisions for road transport and highways, especially monetisation of national highways. Only my previous speaker spoke about the Left-wing extremism identified districts, but while going through the Supplementary Demands for Grants, I find that only Rs. 40 crore have been allocated for them. For Tribal Sub-Plan, which covers those areas and districts which are very much tribal-dominated, a maximum amount of money of Rs. 2,080 crore has been allocated. For Social Justice and Empowerment Ministry, Rs. 2,213 crore have been allocated. I will come to that aspect later, how the Scheduled Caste stipend is not being given to the desirous students. *…(Interruptions)*

Another aspect relating to economic affairs is that for payments towards IMF, due to valuation adjustment, Rs. 9,278 crore have been allocated. I am also of the opinion that for recapitalisation of the public sector banks, a hefty amount of around Rs. 41,000 crore is earmarked. *…(Interruptions)*

Madam Speaker, the total, as I said, is of about Rs. 85,000 crore which is going to be discussed today. Recently, the RBI's report, which was released last Friday, shows that the public sector banks' NPAs are at 14.6 per cent of total advances. It was 11.2 per cent last year and the previous year, it was 9.3 per cent. In 2017-18, it was Rs. 10,39,000 crore and public sector banks accounted for a major chunk of bad loans of around Rs. 8.95 lakh crore. Large value frauds involving Rs. 50 crore and above constituted about 80 per cent of all the frauds during 2017-18. Nearly 93 per cent of the frauds worth Rs. 10 lakh or more occurred in State-run banks. These are the health charts of our banks. It shows how bad the governance is. *…(Interruptions)*

The RBI will continue to monitor asset quality as well as resolution of stressed assets despite the change of the Governor of RBI, but my question is whether the Government has a role in the governance or not. What steps are being taken to improve governance in banks? From symptoms, one knows the disease, but the symptoms are getting treated, not the disease. *…(Interruptions)*

Madam Speaker, the Finance Minister has stated very recently that the Government is working on a single GST rate for most of the goods. Indeed, the top slab of 28 per cent has seen goods moving down to 18 per cent and that is a very welcome step. After cement and auto parts are also transferred to the lower bracket, only luxury and sin goods will remain there. However, there are concerns among the States that their share of GST is not adequate. Odisha's shortfall is around 25 per cent today, which has come down from 31 per cent, and every two months, it is being monitored. Removing goods from the top slab is widely welcomed, but one GST or standard GST goal is an ideal that may be approached but may not be achievable. Rather subsuming various tax slabs into two seems more practical. *…(Interruptions)*

Odisha has been advocating to reduce GST on tendu leaves. It is a minor forest produce. Tribal people collect it. They have a right to procure and sell those products. Since July 2017, 18 per cent GST is levied on tendu leaves. Prior to GST, there was five per cent value added tax on it. *…(Interruptions)*.

Prior to GST, there was five per cent Value Added Tax for it. This hike is too high. It has impacted adversely the social security of 8.5 lakh pluckers, the seasonal workers in Odisha alone. I urge upon the Finance Minister to stand by the Odisha Government in this and support it in the Council.

Madam Speaker, the sharpest decline of poverty level in the country had happened in Odisha. Nearly eight million people have been lifted out of poverty. Around 60 per cent of our population is dependent on agriculture. With the able leadership of Shri Naveen

Patnaik, from a rice-deficit State, Odisha has become the third largest contributor to the Public Distribution System.

Ours is the only State in the country to have doubled the farmers income. In 2014, the BJD had promised additional ten lakh hectares of irrigation and we are almost there. This target will be met by March 2019. To further accelerate agricultural prosperity in the State and to reduce poverty, Naveen Babu has made a historic declaration very recently and that is called KALIA, Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation, amounting to over Rs. 10,000 crore which will be spent in three years for five seasons. All the small and marginal farmers, numbering over 30 lakhs will be covered under the Scheme. An amount of Rs. 5,000 each for kharif and rabi seasons shall be provided as financial assistance for taking up cultivation per family. This will cover 92 per cent of cultivators of the State. This will benefit share croppers, actual cultivators, most of whom own very small extent of land. This is for five cropping seasons spanning three years.

Livelihood support for landless households is also being made with around Rs. 1,250 crore. Financial assistance to vulnerable agricultural households and landless labourers, which are around 10 lakh households, are being covered with a cost of Rs.1,000 crore. I am saying this because we have rural distress and a large number of farmers are in distress today. So, this is the programme which our State Government has implemented. Life insurance cover of Rs. 2 lakh and additional personal accident cover of Rs. 2 lakh is being provided to cultivators and landless agricultural labourers, which is covering 57 lakh households. In addition, crop loan of up to Rs. 50,000 is being provided interest free.

Rural distress is real and its possession is shrouded in the unsubstantiated myth. Finding a realistic and practical solution needs clearing of these cobwebs, not the hubris of campaign. There are about 32 lakh cultivators in our State. Out of this, about 20 lakh cultivators have availed crop loans. This means 12 lakh farmers have not availed crop loan. Out of the 20 lakh loanee farmers, about 60 per cent have regularly repaid their loans. In the scheme of share croppers and landless labourers, farmers are not covered under the loan

waiver scheme. Therefore, we are not in favour of loan waiver *per se*, but there is a necessity to provide adequate support to our farmers and cultivators.

In this context, the KALIA scheme covers 92 per cent of the cultivators and loanee farmers as well as non-loanee farmers, share croppers and landless agricultural labourers. This is a progressive, inclusive and a direct attack on poverty by way of massive investment in this sector and making benefits reach the most needy through Direct Benefit Transfer. Why can the Union Government not accept such programme and extend support? By doing so, this clamour for loan waiver will die down definitely. That is what we are thinking. Telangana State has also covered the distressed farmers to a great extent by their *ryot bandhu* programme. Our State is doing this from our own revenue. We have our ears very much on the ground. Odisha has been repeatedly affected by cyclone, drought and flood.

Despite this, Odisha has managed its finances well. We would not have demanded or demanding for Special Category Status or any funding or assistance from the Union Government. Give us financial autonomy, it would transfer Odisha into the most advanced State in South Asia. At some point of time, our late lamented leader, Mr. Biju Patnaik had said, give me financial autonomy, I will make this State prosper.

Today, we are an emerging State, and we do not require adequate grant or support from what comes through the Special Category Status. Give us that autonomy, it will help us to revive our State's economy, and also make our State one of the prosperous States of South Asia. It would transfer Odisha to the most advanced State. In this Union Government's tenure, one knows how much progress this country has made.

Telecom network, Madam, has grown. No doubt. But to avail connectivity one has to learn to climb a tree as one Minister had said at that point of time or one has to run out of the house or go to the rooftop to get connectivity. So much is the progress!

While travelling in the National Highway, especially in Odisha, I would say, one can very well sense the state of the National Highway without even opening the eyes. From

Rourkela to Cuttack, and up to Balasore or Sambalpur, one can understand what is the problem. That is what development means and that is what has happened in the last four and a half years in Odisha. We need funds for development of telecom facility; we need funds to develop our National Highways.

I come to my last point. We are repeatedly told that with auctioning of coal blocks, Odisha would get around Rs.70,000 crore. Can you imagine how much has been given to Odisha during the last three years? Only Rs.370 crore. Further, the royalty on coal was supposed to be revised upwardly since 2015 but it is not happening. Odisha is being denied its due. A tax for clean energy is imposed. The Union Government has collected Rs.21,000 crore already. How much Odisha has got? Zero. Mahanadi coalfields earns Rs.20,000 crore profit every year. What do we get? Pollution; air is polluted; water is polluted; river is polluted; groundwater is polluted.

Why have you slashed scholarship funds for Scheduled Castes students of our State from about Rs.220 crore per year to just Rs.35-Rs.40 crore? Don't you want meritorious Scheduled Castes students, poor students to be educated? We have raised this issue in this House, and would fight strongly against this anti-Scheduled Castes measures.

Madam Speaker, with these words, I draw the attention of the Finance Minister. These are certain aspects which needs immediate correction. That is the reason why, taking advantage while participating in the Second Supplementary Budget, attention should be paid to the concerns of Odisha; and adequate measures should be made at the earliest. Thank you.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, before me, Shri B. Mahtab has made a very good presentation of the economy of Odisha, and Odisha's economic woes. I will however confine myself to the Supplementary Demands for Grants. The total amount asked for is Rs.85,000 crore, of which the actual outgo will be Rs.15,000 crore; Rs.70,000 will be met by savings from other sources.

Before I go deep into the Supplementary Demands, I want to mention that the Supplementary Demands are being put forward to Parliament in the backdrop of BJP's electoral loss in five States.

They have lost to Congress in three States. Shri Modi ji had spoken about *'Congress Mukt Bharat'* but because of the wrong policies, the Government is taking the Party to a *'BJP Mukt Bharat'*. However, Madam, why did this happen to the BJP is a question on the political economy.

Shri Jaitley under his charge allowed or initiated two cruel steps, as Shri Arvind Subramanian, former Chief Economic Advisor said, one was 'demonetisation' and another is 'hurried implementation of the GST'. Demonetisation took the common people under terrific strain when they had to queue up before the banks and also, hurried implementation of GST put us in a problem where businessmen were not ready to conform to the GST.

We know that, due to demonetisation, thousands of small industries closed down. I have been repeatedly asking from the Government figures of how many people lost their jobs due to the cruel step of demonetisation, the Government has not been able to come forward with an answer. Further, I want to know from the hon. Finance Minister whether he has got any assessment of how many small businesses have closed down due to the hurried implementation of the Goods and Services Tax. I do not think that the Government would come forward with a say.

Madam, I may say that the economy is in a very bad state because the growth in the last quarter of July-September was 7.1 per cent; there is a growth slowdown. This quarter of

July-September showed the lowest possible growth at 7.1 per cent. The Government which used to speak about double-digit growth does not speak about double-digit growth anymore. Madam, the economy is in difficulty. There is a growth slowdown due to tight financial conditions, stressed agricultural sector and slower exports amidst softening global growth conditions. Madam, it would be ambitious to expect any reforms to pick up the economy at the stage.

Madam, I also want to say that the agricultural sector is the worst affected. The farmers are committing suicide all over the country and, so far, the Government has not brought any scheme which can provide hope to farmers.

Madam, in the midst of all this, the Government is using the NITI Aayog to fudge figures. They have said that the new release of GDP back series by NITI Aayog shows a big difference. As Shri Subramanian remarked that NITI Aayog are not the technical experts. They are nobody to give new back series GDP growth figures.

Madam, I spoke about GST earlier. Our Trinamool Congress Party has always said that we are for one tax in the whole nation but we are stuck with five taxes. Now, after almost a year and a half of GST implementation, the hon. Finance Minister is talking about cutting down the number of slabs of taxes to three and he has recently reduced, in the face of coming elections, taxes of some vital commodities but cement still remains at 28 per cent which makes construction costly in this country.

Madam, I would say that we should have an independent fiscal council which will monitor the accounting in real time to find out the actual deficit because the figures the Government is giving out are often misleading.

Having said this, I want to say that out of Rs.85,000 crore, Rs.41,000 crore are being given to banks to recapitalise themselves. If I may say, what is the biggest blunder of the Modi Government? The biggest blunder is demonetisation and hurried implementation of

GST. What is the biggest failure of Mr. Jaitley as Finance Minister? I may honestly say that it is his failure to revive the banking sector.

Madam, for acquisition cost of RBI's stake in National Housing Bank and recapitalisation of public sector banks through issue of government securities, he has given Rs.41,000 crore. Earlier the Government had given Rs.65,000 crore in the Budget. Add Rs.41,000 crore and it becomes Rs.1,06,000 crore. Now out of this, some money has been spent. So, actually Rs.83,000 crore are being given to banks to recapitalise themselves and to bring them up to Basel-III norms.

But, Madam, the problem is not there. You will know that there is a conflict between the Reserve Bank of India, a statutory organisation, and the Government because the Reserve Bank of India has given "Prompt Corrective Action (PCA) on 11 public sector banks. They are not being allowed to lend. They have been told, 'no branch expansion'. The MSMEs are not getting any loans. The banking sector is in doldrums.

Madam, I will just give you one figure. You take interest in economic matters. To show where the public sector has gone, I will just give you one figure. Mr. Finance Minister replied on 21st December, 2018. What is the total figure of non-performing assets (NPAs) of the banks? The NPA was Rs.2,51,000 crore on 31-3-2014 when this Government came to power. What was it on 31-3-2018, in four years? It came up to Rs.9,62,621 crore. It has been a mammoth, gigantic figure.

The Finance Minister is saying that there are some green shoots. National Company Law Tribunal (NCLT) is passing over some stressed assets to the biggest bidder. For instance, Vedanta has bought over Electrosteel; similarly, the Tatas have bought over some steel company. But this is only a small part. At the most they can realise Rs.50,000 crore of stressed assets. …(*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: It does not behove your stature to say this.

The Reserve Bank's asset quality review revealed that this Rs.2.5 lakh crores in 2014 was actually Rs.8.5 lakh crore. The rest was hidden below the carpet.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, as somebody said earlier, the Finance Minister is known to be a glib talker. He is the main defender of the beleaguered Prime Minister. So, he will always say these things.

Under whom did the Reserve Bank of India do asset quality review? It was under … *… who was forced to go by this Government. …(*Interruptions*) He was the Governor and asset quality review was done in his time. Why did this Government ask the Governor, the best economist, to go? …(*Interruptions)*

HON. SPEAKER: Nobody's name can be taken.

… (*Interruptions*)

**प्रो. सौगत राय:** मैडम, हल्ला करने से मेरा गला बंद नहीं होगा। मेरी उम्र ज्यादा है, मैं ज्यादा नहीं चिल्ला सकता हूं। …(व्यवधान) If the musclemen of BJP descend on me, what will I do? I will keep quiet and then start again when they quieten down. …(*Interruptions*) हम बीजेपी के मसलमेन के साथ नहीं लड़ पाएंगे। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You can speak, but do not take anybody's name. That is the only thing.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, lastly, why did Urjit Patel resign? Urjit Patel had come to our Finance Committee. I am not free to disclose what all he said. The man was polite, humble and he had a spine. …(*Interruptions*) A few days after the meeting of our Finance Committee, Urjit Patel resigned much before his term. A new Governor has been appointed. Now, what is the bone of contention? …(*Interruptions*) The Government has shaken all the top institutions. RBI is in doldrums, under attack from the Government. I am not talking of the CBI which is in greater doldrums. I shall discuss CBI on another day. …(*Interruptions*)

So, what happened, Madam? The Government wanted to lay their hands on the golden pot with RBI. What is that? They have got a reserve of Rs. 9 lakh crores. …(*Interruptions*) Now, the Government thinks that if they get more reserves from the RBI, then that will be very convenient for them to make up for the huge non-performing assets of the banks. …(*Interruptions*) Urijit Patel resisted; he had to go. I am saying that any effort to curb the autonomy of the RBI will prove to be suicidal to this country. This is what the Government is doing. That's why they want Rs.41,000 crores and then they will say that we have got so much money from the Reserve Bank of India. …(*Interruptions*)

They are destroying the very basis of the Parliamentary system, especially RBI which has been in existence from 1934 under the RBI Act is being attacked. …(*Interruptions*)

Madam, the other point I want to say is with regard to Air India. Another major failure of this Government is to find a private sector partner for Air India, who is prepared to buy into this airline behemoth. …(*Interruptions*) Nishikant Dubey said Air India is making operating profit. What does it mean? Rs.50,000 crore is the total debt of Air India. Financial turnaround is not …(*Interruptions*)

Madam, I will tell you one more thing. It is not only Air India. My Constituency covers the Dum Dum Airport. Now Jet is reducing routes drastically. Even to Silchar, from 25 flights from Kolkata they have reduced to 11. So, all the airlines are in doldrums. …(*Interruptions*) The Government is now giving Rs.2,345 crores for Air India which is not sufficient. We need a turnaround plan; we need a strategic partner. But the Government is lacking the credibility to find a strategic partner for Air India. …(*Interruptions*)

With two more points, I will conclude. Unlike Mr. Bhartruhari Mahtab, I will not speak at length on the economy of our own State. …(*Interruptions*) I may say that West Bengal has been able to double the farmers' income in this period, whereas the Government wants to double it in 2022. …(*Interruptions*) I am saying the Government has not found a solution for providing minimum statutory price to the farmers. Farmers in Mandsaur in Madhya

Pradesh were shot dead when they were agitating. …(*Interruptions*) The farmers' problems, their suicides, their distress are the biggest problem in this country and this Government has not been able to give anything. …(*Interruptions*)

**15 00 hrs**

Now, this Government has stopped giving NREGA money to the States. In West Bengal, the Chief Minister has said that the State will give NREGA money on its own even if the Centre does not come forward. …(*Interruptions*) But is it fair to deny the States' legitimate share of NREGA fund? No, it is not. Our State Government has waived all revenues …(*Interruptions*) Dubey ji is hinting to the Speaker to stop me. Madam, what to do? I am like a bad penny. …(*Interruptions*) I shall come back. Even if Mr. Dubey and his musclemen throttle me, I shall come back to this House.

I have one last point. The country is in a very bad state. …(*Interruptions*) When demonetisation happened, most of the ministers deserted the Prime Minister, but Finance Minister came along. He came back from surgery and in such a difficult situation, he used to write blogs every day from his glass-enclosed chamber. Why? He is fond of Mr. Modi and wants to defend him. …(*Interruptions*) But how can you defend the indefensible? The Government which has brought the economy to its knees cannot be defended. Passing Supplementary Demands is part of our Constitutional obligation. It will be passed. No Government can run unless there is appropriation from this House. As a very senior Member of this House who has also worked in the Ministry of Agriculture, I would like to point out and draw your attention to the fact that the economy is in doldrums. …(*Interruptions*) I would draw your attention and ask you to pull up the Government to pull up its socks and revive our banking system which is in true difficulty. Banks are not being allowed to lend; Reserve Bank is saying 'prompt corrective action' and Nirav Modi is flying away; Vijay Mallya is flying away; Mehul Choksi is flying away; Lalit Modi is flying away. …(*Interruptions*) There are so many Modis and two Modis have flown away. I don't know

about the third and when he will also fly away from this country. Please rescue the country from the torture and attacks of the Modis. Thank you.

**माननीय अध्यक्ष :** श्री मधुकर कुकडे जी।

**श्री मधुकरराव यशवंतराव कुकडे (भन्डारा-गोंदिया) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सेकेंड सप्लिमेंटरी बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** उनको बोलने का अधिकार है। आप सब ऐसा मत कीजिए, प्लीज़।

…(व्यवधान)

**श्री मधुकरराव यशवंतराव कुकडे :** इस बिल के अंतर्गत सरकार ने किसानों को कोई राहत नहीं दी है। …(व्यवधान) आज देश में किसान मरने की परिस्थिति में हैं। …(व्यवधान) तेलंगाना सरकार ने जिस तरह किसानों को राहत दी है, वैसी ही राहत अगर देश में किसानों को दी जाए, तो लाखों लोग काम करने लग जाएंगे। …(व्यवधान) आज बहुत लोग किसानी से अलग हो रहे हैं। …(व्यवधान) इसकी मुख्य वजह है, स्वामीनाथन आयोग को लागू न करना, किसानों को उचित मूल्य न मिलना, उन्हें 24 घंटे इलैक्ट्रिसिटी न मिलना। …(व्यवधान) अगर हम किसानों की खेती को उद्योग का दर्जा दे दें, हम खेती को उद्योग मान लें, कमर्शियल बैंक्स उनको कर्जा प्राप्त करा दें, तो हर व्यक्ति किसानी कर लेगा। …(व्यवधान) इससे देश की 80 परसेंट आबादी रोज़गार के समीप आ जाएगी। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने किसानों को थर्ड टाइप में डाला है। …(व्यवधान) हमने किसान का अहित किया है। …(व्यवधान) पूरे देश के अंदर कोई भी सरकार रहे, उन्होंने किसानों के हित के लिए कुछ नहीं किया। …(व्यवधान) इस वजह से देश के अंदर किसान किसानी से दूर जा रहे हैं और देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। …(व्यवधान) हम किसानों को कर्जा नहीं देते। …(व्यवधान) कमर्शियल बैंक्स उनको कर्जा नहीं देते। …(व्यवधान) राष्ट्रीयकृत बैंक्स किसानों को कर्जा देते समय दूजा भाव करते हैं, जैसे मानिए कि वे इस देश के नागरिक नहीं हैं। …(व्यवधान) इसीलिए किसानों का अहित हो रहा है। …(व्यवधान) इसलिए मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि सरकार को उनका पूरा कर्जा माफ करना चाहिए। …(व्यवधान) जिस तरह 2009 में यू.पी.ए. सरकार

में डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे और शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, …(व्यवधान) उन्होंने 72 हजार करोड़ रुपये सभी किसानों के माफ किए थे और देश के किसानों को राहत दी थी। …(व्यवधान) हम एक बार किसानों का कर्जा माफ कर दें, उनको 24 घंटे इलैक्ट्रिसिटी दे दें, जैसे तेलंगाना ने किया है, तो देश के किसानों का हित होगा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे क्षेत्र में भेल का कारखाना है जो वर्ष 2003 में भारत सरकार ने शुरू किया था।…(व्यवधान) जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, कम्पाउंड वॉल बनकर काम की शुरूआत हो गई है। मगर जब वर्ष 2014 में यूपीए की सरकार चली गई और एनडीए की सरकार आई तो भेल को सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया। हमारे तब के मंत्री श्री प्रफुल्ल पटेल ने भेल इसलिए लगाया था ताकि हमारे यहां से नक्सलवाद समाप्त हो जाए, किसानों को काम मिल जाए और बेरोजगारी दूर हो जाए।…(व्यवधान) मगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों को धान के लिए 2500 रुपये का भाव दिया है। हमारे यहां भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गडचिरौली धान पैदा करने वाले जिले हैं।…(व्यवधान) हमारे यहां के किसानों के लिए धान का भाव 1740 से बढ़ाकर 2500 रुपये सरकार कर दे, इससे पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। हमारे महाराष्ट्र में प्याज, टमाटर और कपास के लिए दाम नहीं मिलता है।…(व्यवधान) महाराष्ट्र का किसान भारी संख्या में आत्महत्या कर रहा है। हमारे महाराष्ट्र के किसान द्वारा आत्महत्या करने से घर उजाड़ हो रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि किसानों के हित के लिए स्वामीनाथन आयोग को लागू किया जाना चाहिए।…(व्यवधान) अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया तो कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, देश में सुख और शांति रहेगी और देश से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे एक मित्र ने कहा कि मनरेगा घाटे का सौदा है। मैं जिस भंडारा जिले से आता हूं, वहां हजारों लोगों को काम मिलता है। मनरेगा के तहत साल में सौ दिन काम मिलता है।…(व्यवधान) किसान की बहू-बेटियां काम करती हैं, तो उन्हें दाल, नमक और मिर्ची मिलती है। अगर सरकार ने मनरेगा को बंद किया तो किसान आत्महत्या कर लेंगे।…(व्यवधान) हमारे भंडारा और गोंदिया जिले में मनरेगा के तहत अनस्किल्ड लेबर का पैसा दिया गया है, लेकिन काम स्किल्ड का लिया गया है। पूरा काम सीमेंट का हुआ है।…(व्यवधान) इसके लिए केन्द्र सरकार ने एक पैसा नहीं दिया है, जिस कारण से पूरी ग्राम पंचायतें कंगाली की हालत में आ गयी है। ग्राम पंचायतों ने पूरा माल उधारी में लिया है, जिसका दो साल से पेमेंट नहीं हुआ है।…(व्यवधान) ग्राम पंचायतों के ऊपर पूरा कर्ज बकाया है। भंडारा जिले में गोसुखुर्दे प्रकल्प था, जिसको राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित किया था। सरकार ने 90 परसेंट बसा दिया था। यूपीए सरकार के जाने के बाद एनडीए सरकार ने उसे राष्ट्रीय प्रकल्प से निकाल दिया। वहां के 32 गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, लोगों ने मतदान नहीं किया …(व्यवधान)

क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गयीं। उनको खेती का दाम नहीं दिया गया, उनको नौकरियां नहीं दी गयीं, उनके घरों के मूल्य नहीं दिए गए, उनको प्लॉट नहीं मिले। हम जब डैम बनाते हैं तो विस्थापित लोगों को सुविधाएं देना हमारा काम है।…(व्यवधान) वर्ष 2014 के पूर्व वह राष्ट्रीय प्रकल्प था, लेकिन सरकार बदलने के बाद उसको राष्ट्रीय प्रकल्प से निकाल दिया गया। आज भंडारा जिले का गोसुखुर्दे प्रकल्प 20 साल से पूरा नहीं हो रहा है।…(व्यवधान)

महोदया, हमारे यहां तेंदू पत्ता होता है। तेंदू पत्ते के लिए हजारों लोग काम करते हैं। हम उनके लिए कोई सुविधा नहीं करते हैं।…(व्यवधान) जीएसटी के कारण सारे उद्योग खत्म हो गए हैं। छोटे व्यापारियों को जीएसटी अंग्रेजों का काला कानून जैसा लगता है। जब अंग्रेज लोग थे तो वे दमन की नीति बनाते थे, वैसे ही जीएसटी के कारण छोटे उद्योग वाले मर रहे हैं। व्यापारी इससे डर रहा है।…(व्यवधान) ऐसा मान लिया गया है देश का व्यापारी चोर है, वे चोरी करते हैं, गुनहगार हैं, डाकू हैं, उन्हें अंदर करने की बात करते हैं।…(व्यवधान) इसी कारण से जीएसटी का कानून जनता के ऊपर काला कानून हो गया है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, नोटबंदी के तहत किसकी नोटबंदी हुई? नोटबंदी हमारी नहीं हुई, बल्कि जो महिला काम करती है, …(व्यवधान) किसान की औरतें काम करती हैं, हमारे घर की औरतें जो पैसा बचाकर बच्चों के लिए रखती है, शादी के लिए रखती है, …(व्यवधान) उनके 500 और 1000 रुपये के नोट पर नोटबंदी करके आपने देश की पचास प्रतिशत महिलाओं के साथ अन्याय किया है। जितनी भी महिलाएं थीं, उनके लिए आपने नोटबंदी की थी।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, पिछली केन्द्रीय सरकार ने हमारे यहां दस बेड अस्पताल चलाने का काम शुरू किया था।…(व्यवधान) उनसे अनुसूचित जाति और देहात के लोगों को इलाज और सुविधाएं मिलतीं, लेकिन सरकार ने 21.03.2018 को वे पूरे अस्पताल बंद कर दिए।…(व्यवधान) क्योंकि उनको यूपीए की सरकार ने चालू किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था और बाबा साहेब अम्बेडकर …(व्यवधान) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को दवाई मिले, डिस्पेंसरी की सुविधा मिले। इसमें लाखों लोग काम कर रहे थे। डॉक्टर्स, नर्स और अन्य कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन उसको 21.03.2018 को बंद करके, देश में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय किया गया है।…(व्यवधान)

हमने पूरे भारतवर्ष में अनुसूचित जाति के लोगों को सुविधा दी। …(व्यवधान) हम बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का वादा करते हैं।…(व्यवधान) हमने एक तरफ संविधान का खून किया हुआ है। …(व्यवधान) हमने उस

माध्यम से संविधान का हनन किया हुआ है।...(व्यवधान) जो ज़्यादातर लोग यह काम करते हैं, हमने यह प्रयास किया है कि वे लोग काम नहीं करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, रेलवे के अंदर भर्ती हुई।...(व्यवधान) हमने कहा भर्ती नहीं करेंगे।...(व्यवधान) सरकार ने आदेश दिया कि भर्ती करो। 20 परसेंट एडिशनल कोटा है। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उनको नौकरी पर लो तो भी सरकार रेलवे में भर्ती कर नहीं रही है।...(व्यवधान) एक तरफ माननीय प्रधान मंत्री जी नौकरियों के बारे में बात करते हैं।...(व्यवधान) आज भी रेलवे में नौकरी नहीं है। रक्षा मंत्रालय में लोगों के इंटरव्यू हुए, सेलेक्शन हुआ और तीन साल से उन बच्चों को नौकरी नहीं दी।...(व्यवधान) पूना के लड़के मेरे गाँव के लड़के हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि सरकार की क्या नीयत है। ...(व्यवधान) लड़कों ने परीक्षा पास की, रिजल्ट आ गया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, हम स्वीकार करते हैं कि समाज के अंदर आज अंतर्विरोध है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ प्याज वाले किसान हैं। उनकी नहीं सुनी गई। ...(व्यवधान) हर किसान को कम से कम प्रति क्विंटल 2000 रुपये देना चाहिए और 2000 रुपये क्विंटल देंगे तो हमारा किसान खेती कर सकेगा, अन्यथा हमारे उत्तर नासिक और पश्चिम नासिक के प्याज वाले किसान आत्महत्या करेंगे।...(व्यवधान) हमारा आपसे अनुरोध है कि आज बिल के माध्यम से सरकार को आदेश दीजिए कि हमारे प्याज किसानों को दो हजार रुपये क्विंटल मिले, जिससे किसानों को राहत पहुँच सकें।...(व्यवधान) माननीय शरद पावर जी हमारे कृषि मंत्री हैं, उनका नाम और इसी आशा के साथ मैं आपनी बात को खत्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत।

DR. P.K. BIJU (ALATHUR): Madam Speaker, I strongly oppose the Supplementary Demands for Grants presented before this House.

Madam, the present Government has failed to keep its promises made in their election manifesto as well as in the presentation of Budget in this House from time to time. We all know about the elections held in five States. The BJP has lost heavily in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. In the last Budget, they claimed that they were in favour of farmers and agriculture. But, they have failed to save the agriculture and farmers in this

country. The suicides of farmers are continuing and the distress among farmers is going up every day. After the election result, the newly formed Government has started some measures and now, the BJP Government is doing it, that is, writing off the loan to safeguard the farming community.

Madam Speaker, in the last Budget, in agriculture and rural development, the percentage of GDP has reduced from 1.15 per cent to 1.08 per cent. The farmers of our country are left high and dry. The contribution of agriculture sector to the Indian economy is now hovering around 60 per cent only. According to the Economic Survey, in the Financial Year 2017-18, the sector's growth has fallen from 4.9 per cent in the Financial Year - 2016-17 to 2.1 per cent in the Financial Year - 2017-18.

Madam Speaker, we have allotted about Rs. 9 lakh crore, Rs. 10 lakh crore and Rs. 11 lakh crore in each Budget, but where is the money going? That is not benefiting the farmers and the farming community. Recently, the Centre for the Study of Developing Societies (CSDS), based in Delhi, released a report stating that 76 per cent of the farmers want to give up farming. It is a very sensitive matter. Without farming community, how can we develop our country? More than 60 per cent of our people are still dependent on farming and allied industries.

So I would request the Government to look at the agriculture sector seriously. The distress of farmers would increase if the prices of onion are reduced to less than Rs.1. We had witnessed a long march of the farmers in Maharashtra. The farming community staged a dharna in Rajasthan and other parts of the country. …(*Interruptions*)

The second point which I want to present before this august House is regarding the job situation in the country. Earlier the manifesto of the BJP claimed that they would give two crore jobs to the jobless people, particularly the youth of this country. But now we are approaching the end of the term of this Government in the next 4-5 months. What is the status of job growth in this country? The rate of unemployment has increased from 3.6 per

cent to 4.85 per cent. They claimed that they would give two crore jobs each year which means ten crore jobs should have been given in five years to the youths of this country. I would request the Government to increase the number of jobs. You should create jobs for the youth and poor of this country. Then only they can survive. …(*Interruptions*)

What is happening now? Our economy has gone completely in the hands of corporates. Of the wealth generated in 2017-18, 78 per cent has gone to one per cent of the corporates in this country. In 2014-15, it was 53 per cent. I think this will further increase which means the majority of population will be deeply affected. Their day-to-day lives will be affected in the coming years. …(*Interruptions*)

This Government has failed to control the economic situation in this country. The present Government has claimed that we are the sixth largest economy in the world. Then why are we approaching RBI and asking for their reserve fund? Around Rs. 9.65 lakh crore are reserved in the Reserve Bank of India. In the history of this country, this reserve has never been taken except once. We had taken money from that reserve fund in the Indo-China war period. Now you are asking for Rs.3.6 lakh crore from the reserve fund of RBI. …(*Interruptions*)

You are claiming that you are growing and that you are the sixth largest economy in the world. Then why are you asking for money from the reserves of the RBI? The former RBI Governor, Shri Urjit Patel, resigned. You had appointed him in your tenure. Now you have appointed a historian in his place as the Governor of RBI. Your MP from the other House, publicly stated that he was a corrupt officer. You are claiming that you are against corruption. Then why have you put a corrupt officer as a leading functionary of this country? …(*Interruptions*)

Now our NPAs are growing. The media reports say that it is around Rs.11 lakh crore. I do not know the exact figure. The Government has not revealed anything. The

NPAs are increasing. Then you want money from the reserve fund of the RBI and from the common people of this country. …(*Interruptions*)

These two things are not matching. I would like to request the Government to give details about what is happening to the economy of this country.

Finally, I would like to make a point on the NREGA. This would help reduce joblessness in rural India. I would also like to request the Government to increase the number of man-days from 100 days to 200 days. That will give some relief to the common people in the country.

With these words, I oppose the Supplementary Demands for Grants.

Thank you.

**श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम):** मैडम, मेरे संसदीय क्षेत्र 27, मुम्बई उत्तर पश्चिम तथा महाराष्ट्र राज्य के लिए संबंधित निम्नलिखित सूचना एवं मांग, जिसका बजट 2018-19 में समावेश हो, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी के ध्यान में लाकर उन्हें तुरन्त लागू करने की विनती करता हूं।…(व्यवधान)

महोदया, वर्सोवा, अंधेरी पश्चिम, मुम्बई समुद्री तट पर मछुआरों का फिशिंग का बिजनेस चलता है। पर, वहां पर बहुत सालों से जो मलबा जमा हुआ है, उसके कारण कई नौकाएं फंस जाती है, जिससे मछुआरों को वित्तीय हानि होती है।…(व्यवधान) इसमें मछुआरे अपनी जान भी गंवा देते हैं।…(व्यवधान) मेरी मांग है कि यहां के मलबे की सफाई यानी ड्रेजिंग के लिए 80 करोड़ रुपये के प्रावधान की जरूरत है।…(व्यवधान) उसके जेट्टी के पुनर्निर्माण हेतु 350 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध की जाए।…(व्यवधान) इससे संबंधित मत्स्य प्रशिक्षण संस्थान के विकास के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध करा कर उक्त संस्था को मुम्बई से अन्यत्र स्थानांतरित न किया जाए।…(व्यवधान)

मुम्बई स्थित लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी पश्चिम में डाक भवन के लिए आरक्षित भूमि पर तुरन्त डाक भवन का निर्माण हो और उसके लिए आवश्यक निधि मंजूर की जाए।...(व्यवधान) साथ ही साथ, मोतीलाल नगर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव पश्चिम पूर्णत: ढह चुका है।...(व्यवधान) इसके लिए भी तुरन्त निधि उपलब्ध करा कर उसे आबंटित की जाए।...(व्यवधान)

इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ई.एस.आई.सी.) अस्पताल, मरोल, अंधेरी पूर्व, मुम्बई को हाल ही में आग लगने के कारण बंद करना पड़ा।...(व्यवधान) इसमें नौ लोगों की मौत हो गयी।...(व्यवधान) इस अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए अधिक से अधिक निधि उपलब्ध की जाए।...(व्यवधान) साथ ही साथ, यहां के शेष 100 कर्मचारियों को वादों के मुताबिक केन्द्र सरकार के अधीन समाविष्ट किया जाए।...(व्यवधान)

छत्रपति शिवाजी महाराज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है, किन्तु इस परियोजना में बाधित लगभग 18 हजार झुग्गियों में रहने वाले पात्र नागरिक पुनर्वसन की प्रक्रिया में गत तीन वर्षों से प्रतीक्षा में हैं।...(व्यवधान) इसके लिए आवश्यक निधि तुरन्त आबंटित कर उनका पुनर्वसन किया जाए।...(व्यवधान)

पश्चिम उपनगरीय रेलवे में 'राम मंदिर' नाम का रेलवे स्थानक है।...(व्यवधान) उसके नजदीक रेलवे के सीमेन्ट गोडाउन के कारण काफी मात्रा में प्रदूषण हो रहा है और उसके परिसर में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है।...(व्यवधान) जनता की मांग को देखते हुए इस सीमेन्ट गोडाउन को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए।...(व्यवधान) इस स्थान पर गोरेगांव और जोगेश्वरी के बीच में जोगेश्वरी टर्मिनस के निर्माण का कार्य होना चाहिए, यह मेरी मांग है।...(व्यवधान)

मुम्बई उपनगरीय रेलवे यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए रेलवे की रिक्त जमीन पर यात्री सुविधा केन्द्र का निर्माण कर रेल पटरियों के दोनों ओर रेलवे की जमीन पर बसे झुग्गीवासियों का पुनर्वसन किया जाए।...(व्यवधान)

मुम्बई उपनगरीय रेल पटरियों के दोनों ओर काफी संख्या में नागरिकों की बसावटें हैं और वहां झुग्गियां बसी हैं।...(व्यवधान) वहां कोई भी सुरक्षा दीवार न होने के कारण सभी रेल यात्री उक्त रेलवे स्थानक पर आने-जाने हेतु इस रेल पटरी का इस्तेमाल करते हैं।...(व्यवधान) इसके कारण कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं।...(व्यवधान) इस पटरी की बाजू में सुरक्षा वाली कम्पाउंड दीवार बनाने के लिए पैसे का आबंटन करना चाहिए।...(व्यवधान)

यह मांग लेकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।...(व्यवधान)

**श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ):** अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस अनुपूरक बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।…(व्यवधान) मैं इसका विरोध यूं ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि आज से पांच साल पहले जब देश के अंदर लोक सभा का चुनाव हो रहा था और उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प-पत्र था, उस पर देश के जन-मानस ने भरोसा किया था।…(व्यवधान) अभी तक पूरे के पूरे पांच बजट पेश भी हो गए, पास भी हो गए और खर्च हो गए, लेकिन देश के अंदर एक भी समस्या नहीं घट पाई,…(व्यवधान) बल्कि दिन-प्रतिदिन तथा साल-दर-साल समस्याएं बढ़ती गईं।…(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं कहां-कहां से शुरू करूं, अगर मैं किसान भाइयों की ओर से बात शुरू करूं, तो इनके वादे थे कि डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देंगे, दोगुनी लागत करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। ये वादे तथा संकल्प-पत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी आई थी, लेकिन आज आपको सूचित करते हुए बहुत अफसोस होता है कि एनडीए की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 60 हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं।…(व्यवधान) 60 हजार किसानों के आत्महत्या करने के बाद इन्होंने जितनी बातें की थी, इन्होंने कहा था कि हम किसानों को समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन आज पूरे उत्तर भारत के अंदर कोल्ड स्टोरेज से आलू को बुरी तरह से फेंका जा रहा है।…(व्यवधान) आज किसानों को आलू का मूल्य नहीं मिल रहा है। प्याज के मूल्य के नाम पर गुजरात के अंदर 55 पैसे प्याज का मूल्य दिया गया।…(व्यवधान)

वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में गन्ने के नाम पर जो बातें की गई थी, आज गन्ने के मूल्य की हालत बहुत ही खराब है।…(व्यवधान) मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का भुगतान करीब दस हजार करोड़ रुपये बाकी है।…(व्यवधान) आज जहां गन्ने का मूल्य 305 रुपये घोषित है, लेकिन किसी भी किसान को सौ रुपये से ऊपर नहीं मिल पा रहा है। देश के किसानों की यह सच्चाई है।…(व्यवधान) इसी तरह हर साल पचास लाख किसान खेती तथा किसानी का काम छोड़ रहे हैं। एनडीए की सरकार ने किसानों की यह हालत कर दी है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, नोटबंदी के समय बहुत बातें कही गई थीं। उस समय कहा गया था कि हम नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार रोक देंगे। नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी के बाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा।…(व्यवधान) इन्हीं बातों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम देश को कड़वा घूट पिला रहे है, कड़वी दवा पिला रहे हैं, लेकिन यह कड़वी दवा देश की किसी भी बीमारी को खत्म नहीं कर पाई, बल्कि देश के अंदर सात करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए।…(व्यवधान) प्राइवेट कंपनियों में छंटनी हो गई। हमारे देश में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या थी। उस समस्या का नोटबंदी तथा जीएसटी के बाद निराकरण नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद से समस्या फंसी ही है।…(व्यवधान)

उसके बाद जीएसटी भी एक गंभीर मुद्दा है। किसानों को खेती के उपयोग के लिए जहां ट्रैक्टर पर जीएसटी 28 फीसदी है, वहीं हीरे के कारोबार करने के लिए जीएसटी केवल पाइंट 25 फीसदी है।…(व्यवधान) यह देश की सच्चाई है। यह सरकार किसानों की कितनी समर्थक है, यह हमारे सामने है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी, तो केवल 49 परसेंट एफडीआई पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हंगामा खड़ा कर रहे थे, लेकिन आज हंड्रेड परसेंट एफडीआई को एंट्री दे दी गई है।…(व्यवधान) हंड्रेड परसेंट एफडीआई के बाद देश के अंदर खुदरा व्यापारी पूरी तरह से चौपट होने के कगार पर खड़े हैं।…(व्यवधान) आने वाले समय में देश के सामने जो परिस्थितियां आएंगी, उनमें देश का खुदरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाएगा।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

**श्री धर्मेन्द्र यादव :** अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यह बड़ा गंभीर मुद्दा है और आखिरी सप्लीमेंट्री है। महंगाई के मुद्दे पर जब पेट्रोल 55-60 रुपये था, उस समय देश में हंगामा किया जा रहा था, डीजल के नाम पर हंगामा किया जा रहा था, गैस सिलेंडर के दाम पर हंगामा हो रहा था, लेकिन आज पेट्रोल लगभग 85 रुपये तक पहुंच गया है और डीजल भी पहुंच गया है।…(व्यवधान)

उज्ज्वला योजना के नाम पर बहुत ऊंची-ऊंची बातें हुई, लेकिन इस योजना के बाद आज सिलेंडर का रेट एक हजार रुपये से ज्यादा हो गया है।…(व्यवधान) आज सच्चाई यह है कि उज्जवला योजना के तहत जिनको सिलेंडर मिला था, वे अपने सिलेंडर को दोबारा भरवा नहीं पाएं।…(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आजादी के 70 सालों के बाद पहली बार यह हुआ है कि देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं भी संकट में हैं। आरबीआई जैसी संस्था भी संकट में है। आपकी सरकार में दो-दो गवर्नर छोड़कर चले गए। यह कोई मामूली संकट नहीं है।...(व्यवधान) आज जिस तरह से सरकार चल रही है, उससे आने वाले समय में देश के सामने आर्थिक संकट भी आएंगे, रोजगार के भी संकट आएंगे, किसानों के भी संकट आएंगे और बेरोजगारी भी बढ़ेगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आज देश के सामने जो संकट है, मैं उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इनकी सरकार के कार्यकाल में लगभग पांच लाख साक्षर अनुदेशक बेरोजगार हो गए हैं।...(व्यवधान) अगर अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इनके कार्यकाल में एक लाख बहत्तर हजार शिक्षा मित्र बेरोजगार हुए हैं।...(व्यवधान)

कर्मचारी लोग अपनी पेंशन के लिए परेशान हैं। जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, उसे पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करिए और जो नई पेंशन व्यवस्था है, इस व्यवस्था को खत्म करिए। एफडीआई के नाम पर, महंगाई के नाम पर, तमाम गन्ना किसान और तो और ...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, किसानों की आंखों में दिन में धूल झोंकी जा रही है। डीएपी और यूरिया का रेट घटा दिया गया। यूरिया का एक कट्टा जो 50 किलोग्राम का होता था, उसे 45 किलोग्राम का कर दिया है। एनडीए के लोग, क्या आप समझते हो कि किसानों की आंखों में धूल झोंक लोगे? देश का किसान इस समय परेशान है। यही कारण है कि पांचों राज्यों में आप हारे हैं और आने वाले वर्ष 2019 के चुनावों में इसी तरह से पूरा देश हारोगे, क्योंकि आपकी नीतियों से आपके कार्यक्रम से देश का जनमानस आज परेशान है। आपने जो वादे किए थे, उन वादों को आप भूल गए। आपने जनता के विरोध में काम किया है। जनता आने वाले समय में आपको माफ नहीं करेगी।

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Thank you, Madam Speaker.

Madam, on behalf of my Party, TRS Party, I rise to support the Supplementary Demands for Grants. This is the second batch of Supplementary Demands for Grants which we have to pass. The Parliament should authorise the Government in respect of these Demands.

Madam, I would like to suggest one or two points which are very important. Demand no. 58 is with regard to the higher education.

**15 31 hrs**

*At this stage, Shri* D.V. Sadananda Gowda *and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

In the Telangana State, we have formed some new districts. Earlier, there were ten districts. Now, we have formed 31 districts. We made a request to the hon. Minister of Human Resource Development many a time to establish Navodaya Vidyalayas in each district. The policy of the Government is that every district should have a Navodaya Vidyalaya. But, in these Supplementary Demands for Grants, it is very unfortunate that I could not see any allocation for that. The assurance given by the Government was that the Government would initiate the process of establishing the Navodaya Vidyalayas in new districts. Earlier, the Government had established Navodaya Vidyalayas in those districts which were formed till 2014. From 2014, the districts formed in various States were not given these Navodaya Vidyalayas.

Therefore, I request the hon. Finance Minister to make some provisions in the Supplementary Demands for Grants for establishing these Navodaya Vidyalayas in newly formed districts in all the States.

I would like to suggest one more thing. We have to take into consideration the best practices adopted by different States. I would like to suggest two schemes which were launched in our State by our hon. Chief Minister, Mr. K. Chandrashekar Rao *garu.* The first Scheme is with regard to farming community. Many speakers spoke about distress among the farmers. We have evolved a Scheme known as Rythu Bandhu, in which there is a provision of direct benefit transfer to the farmer's account of Rs. 8,000 per year, that is, Rs. 4,000 for each crop. Another Scheme is Rythu Bima. We have paid an amount of Rs. 900

crores as premium to the LIC where every farmer is insured by the LIC irrespective of the cause of death. Unfortunately, if an elder member in a family dies, Rs. 5 lakh is being paid to his family by the LIC.

These two Schemes are benefitting a lot to the farming community. I think, the national political parties, both, BJP and Congress, should think over it. They are going to form a new Government. I do not know, which party will form the Government. The people will elect them. At least, the political parties should think about these two Schemes which are the best practices adopted by our State Government.

Thank you, Madam.

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर):** अध्यक्ष महोदया, मैं यहां इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझसे पहले के वक्ताओं और विशेषतौर से निशिकान्त जी ने जिस तरह से कुछ बातों की सच्चाई हमारे सामने रखी है, …(व्यवधान) आज विपक्ष की सीटें भी खाली नजर आ रही हैं। जो इकोनोमी पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, All I want to say is this. All the fundamentals of the Indian economy are strong and robust be it inflation, be it current account deficit, be it fiscal deficit, be it foreign direct investment or foreign exchange assets. On the contrary, under the UPA rule, India was reduced to 'fragile five' and under Modi *ji*'s leadership, India is among the world's top six economies. Let me congratulate the Government on that.

मुझे लगता है कि ये आंकड़ा दिखाते हैं …(व्यवधान) अगर आप फिसकल डेफिसिटी की बात करें तो यूपीए के समय 6.8 प्रतिशत से नीचे नहीं आती थी लेकिन आज यह चार प्रतिशत से नीचे है यानी 3.8 प्रतिशत पर है। करेंट डेफिसिट एकाऊंट सबसे कम स्तर पर आकर खड़ा है। आज के समय जब हम वित्तीय वर्ष में फिसकल डेफिसिटी की बात करते हैं, यह लगभग 3.3 फीसदी का टारगेट रखा गया है …(व्यवधान) जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही नहीं, अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले बैंकों के नॉन परफार्मिंग एसेस्ट्स की बात कही। एक माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनको कुछ सदस्य गुगल अंकल कहते हैं, …(व्यवधान) लेकिन जिस तरह से गूगल असत्य झूठी खबरें देता है, इस पार्लियामेंट के गूगल अंकल ने बहुत सारी बातें झूठी कही हैं। …(व्यवधान)

मैं उनको याद कराना चाहता हूं, जब कालेधन पर चर्चा हुई थी तब उनकी पार्टी की मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के मंत्री और सदस्यों के नाम सबसे पहले आए थे। आज वह अपना बचाव करने के लिए सदन में नहीं हैं लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एनपीए यह किसी और की देन नहीं है। यह पिछली यूपीए सरकार की देन है, जिन्होंने अलग-अलग नीतियां बनाकर ऐसे उद्योगपतियों को पैसे दिए, जिन्होंने देश का पैसा वापस नहीं किया बल्कि देश का पैसा लेकर वे रफूचक्कर हो गए और देश से बाहर चले गए। …(व्यवधान)

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने फ्यूजीटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल लाकर न केवल देश का पैसा वापस लाने का काम किया है बल्कि उन भगौड़ों को भी वापस लाने में मोदी सरकार सफल हुई है। यह हमारी प्रतिबद्धता है कि जो लोग देश का पैसा लेकर रफूचक्कर हुए हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे और देश का एक-एक पैसा देश के खाते में वापस लाएंगे। यह एनपीए यूपीए सरकार की देन है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिर पिछली सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने देश को गुमराह किया। आप कृपया देश के सामने असली आंकड़े रखिए कि यूपीए सरकार के समय कितने लाख करोड़ रुपये का ऋण उन व्यापारियों को दिया गया, जो आज इतना एनपीए हो गया है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने देश से झूठ क्यों बोला? आप कृपा करके देश के सामने सच्चाई लाइए। आपने जो भी प्रयास किए, चाहे वह इन्सॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के माध्यम से किया हो, आज लाखों करोड़ रुपये बैंकों का आया है। आपने उन उद्योगपतियों को भी वापस कंपनी खरीदने से रोका है, जो कल तक लोन लेते थे और पैसा डकार जाते थे और फिर पैसा लेकर खुद मालिक बन कर बैठते थे। इससे आज की सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है। एक ओर उद्योग को बचाने और कर्मचारियों को लगातार रोजगार देने की प्रतिबद्धता है, वही दूसरी ओर ऐसे व्यापरियों से मुक्ति दिलाने की भी है। आपके नेतृत्व में जहां फिसकल डेफिसिट, करेंट एकाऊंट डेफिसिट में रिकार्ड कमी हुई है, इससे अच्छी फिसकल मैनेजमेंट न पहले थी …(व्यवधान) न है। देश आगे और अच्छा करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

मैडम, जहां सत्रह से ज्यादा टैक्सेसज थे, 1150 चुंगी नाके थे, इन सभी को आप खत्म करके जीएसटी लेकर आए हैं, 'वन नेशन वन टैक्स' के कारण देश को लाभ हुआ है। कुछ लोगों का देखने का नजरिया नहीं बदला है और वह अपने उस समय की सरकार के नजरिए से देखते हैं, जब व्यापरियों से लूट होती थी और व्यापरी तंग होता था, लेकिन आज व्यापारियों को भी लाभ मिला है और देश भी आगे बढ़ा है।

…(व्यवधान) टैक्स कलेक्शन, जो कल तक मात्र 3.8 करोड़ लोग टैक्स देते थे। आज लगभग 6 करोड़ 80 लाख लोग टैक्स देते हैं। यह बढ़ोतरी पिछले 2 वर्षों में हुई है। जहां 6 लाख करोड़ टैक्स इकट्ठा होता था। …(व्यवधान) आज साढ़े 10 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स इकट्ठा होता है। इस शानदार काम के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से कुछ प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा। आखिर पिछली सरकार की ऐसी कौन-सी मजबूरियां थीं जो एन.पी.ए. के एकाउंट्स को इन्होंने झूठ बताया और सही फिगर देश के सामने नहीं रखी। 80-20 स्कीम जिसकी बार-बार चर्चा होती है, आखिर 80-20 स्कीम के तहत किन लोगों को लाभ मिल रहा था? ...(व्यवधान) ऐसी क्या मजबूरी थी कि सरकार जाते-जाते ऐसी स्कीम को लेकर आई, जिससे गिने-चुने उद्योगपतियों को लाभ मिला और भारत सरकार को चूना लगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं, कृपया करके अगर सदन को कुछ जानकारी देंगे कि इससे कितना नुकसान देश को हुआ है, तो इससे देश को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ...(व्यवधान) एक डॉलर कमाने के बदले में क्या भारत सरकार को 212 रुपये अपनी ओर से देने पड़े? अगर ऐसा था तो इस 212 रुपये की सब्सिडी के बदले भारत को कितना नुकसान हुआ और इससे किन व्यापारियों को लाभ हुआ? कृपया करके उनके बारे में भी बताएं। ...(व्यवधान) जब डायमंड की बात आती है, तब 2012 में इसकी अलग-अलग क्लासीफिकेशन थी, नैचुरल की और मैन मेड की भी। ...(व्यवधान) दोनों पर अलग-अलग तरह के टैक्सेज थे। आखिर ऐसा क्या हुआ, पिछली सरकार ने किन लोगों को लाभ देने का प्रयास किया, जो आज देश से बाहर भी हैं। काम इनके गलत थे लेकिन ठीकरा आज की सरकार पर फोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं चाहता हू माननीय वित्त मंत्री जी देश को सच्चाई बताएं। ...(व्यवधान) जहां ड्यूअल फ्रेट की बात है, क्या इसमें सच्चाई नहीं कि डॉमेस्टिक फ्रेट जो आयरन ओर का था, वह भी पिछली सरकार के समय आयरन ओर के लिए अलग-अलग नीति बनाई गई, क्या सी एंड एजी की रिपोर्ट में यह नहीं आया कि इससे 30 हजार करोड़ रुपये का नुकसान देश को हुआ? ...(व्यवधान) आखिर पिछली सरकार ने ऐसे कदम क्यों उठाए, जिससे देश का नुकसान हुआ? पिछली सरकार में दम नहीं था। हमारी सरकार ने इस पर सी.बी.आई. की जांच भी बैठाई है। इससे पता चलता है कि हमने ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास किया है। ...(व्यवधान) यही नहीं, जहां तक चिट फंड की बात है, अभी कुछ देर पहले सौगत राय जी कह रहे थे, बड़-बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन इनके मुख्यमंत्री की पेंटिंग एक चिट फंड की कंपनी वाला 3 करोड़ रुपये में खरीदता है। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? इनके सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद होते हैं।...(व्यवधान) गरीब आदमी का करोड़ों रुपये चिट फंड के नाम पर डकार गये, चाहे वह शारदा हो या नारदा हो, अगर ऐसी कंपनियों को भी बंद करने का काम और इनके खिलाफ कार्रवाई किसी ने की है, तो वह काम हमारी सरकार नरेन्द्र मोदी की सरकार ने किया है।...(व्यवधान) मुझे पूर्ण विश्वास है कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर अगर सरकार कोई कानून लाएगी, तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या छोटे या उन लोगों को जो पैसा कमाने के चक्कर में अपना पैसा ऐसे लोगों के पास जमा करवाते थे, जो चिट फंड के नाम पर पैसा लेकर छू मंतर हो जाते थे। क्या आप अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर नया कानून आएंगे? ...(व्यवधान) अगर लाएंगे तो आप इस सदन को आश्वस्त कीजिए ताकि करोड़ों लोगों को भविष्य में अपने पैसों का ऐसी फर्जी स्कीमों के माध्यम से नुकसान न हो।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने कुछ और बातें रखना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आज कहा गया कि क्या स्कीमों का लाभ मिला, मैं यह कहूंगा कि योजनाएं पहले भी चलती थीं, योजनाएं अब भी चल रही हैं। फर्क बस इतना है पहले लोग यह पूछते थे कि 'कितनों को मिला लाभ, कितनों को मिला लाभ' अब पूछते हैं 'कहीं कोई रह तो नहीं गया, कहीं कोई रह तो नहीं गया'। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। पहले कितने लोगों तक पहुंच पाता था, यह पता नहीं। ...(व्यवधान) लेकिन, आज मैं यह कह सकता हूं कि 2014 में मात्र 50 परसेंट लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्रों सेन्सिटाइजेशन की सुविधा थी। आज लगभग 90 प्रतिशत से ज्यादा के पास है। ...(व्यवधान)

वर्ष 2014 में मात्र 70 प्रतिशत घरों के पास बिजली थी, आज शत-प्रतिशत घरों तक बिजली पहुंचाई है तो नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पहुंचाई है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। ...(व्यवधान) लगभग 32 करोड़ एलईडी बल्ब्स देकर, इस योजना के माध्यम से गरीब और आम परिवारों का पैसा बचा, वहीं साढ़े सोलह हजार करोड़ रुपये की बचत बिजली के बिलों में हुई है। ...(व्यवधान) यह हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान है। ...(व्यवधान)

जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय की बात है, पहले स्टेंट के प्राइसेज कम किए गए, दवाइयों के दाम कम किए गए। ...(व्यवधान) नड्डा जी यहां मौजूद हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अब 'आयुष्मान भारत' के माध्यम से हिन्दुस्तान के 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये के इलाज की सुविधा मुफ्त में देने का जो वादा माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में किया था, उसको पूरा किया गया है। ...(व्यवधान) मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। ...(व्यवधान) यह देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ...(व्यवधान) मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 'आयुष्मान भारत' के अंतर्गत कितने हजार करोड़ रुपये का खर्च होगा और इतने ज्यादा परिवारों को जो लाभ कोई सरकार पिछले 70 वर्षों में नहीं दे पाई, आखिर हमारी सरकार ने मात्र पांच वर्ष के अपने कार्यकाल में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया है, वह आप कैसे कर पाए? ...(व्यवधान) इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। ...(व्यवधान) मैं यही कहूंगा :

"नीति नहीं, नया विश्वास, पूरी हो रही जनता की आस।
बढ़ रहा योजनाओं का दायरा, छंट रहा अंधेरा,
हुआ नया सवेरा, हुआ नया सवेरा। "

माननीय वित्त मंत्री जी, आपने अलग-अलग मंत्रालयों के बजट में धन का प्रावधान करके, बजट का प्रावधान करके वह सब कुछ उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है, जो पहले संभव नहीं हो पाया। …(व्यवधान)

आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में लगातार देश की इकोनोमी आगे बढ़ी है। जहां कांग्रेस के कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में यह मात्र 4.8 फीसदी तक सीमित हो गई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके नेतृत्व में यह 7.5 फीसदी से आगे बढ़ी है और दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनोमी बनी है। …(व्यवधान) इसके लिए मैं आपको और सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। …(व्यवधान) अभी विपक्ष के एक नेता कह रहे थे कि काला धन, डिमॉनेटाइजेशन और जीएसटी के आने से क्या हुआ है। …(व्यवधान) मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच्चाई नहीं है कि नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और पथराव जैसी घटनाओं में पहले से कमी आई है? …(व्यवधान) अगर कमी आई है तो यह इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। …(व्यवधान) पहले रियल इस्टेट के फेक रेट्स रहते थे, कीमतें बढ़ी हुई रहती थीं, आम आदमी घर या फ्लैट खरीद नहीं सकता था, क्या उसमें भी कमी नहीं आई है? …(व्यवधान) अब आम आदमी की पहुंच में घर आए हैं। महंगाई पर भी अंकुश लगा है। …(व्यवधान) पहले जो महंगाई कांग्रेस के समय में डबल डिजिट में रहती थी, हमारी सरकार के समय चार फीसदी से कम महंगाई की दर आई है। …(व्यवधान) इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को और मोदी सरकार को बहुत-बहुत बधाई समस्त सदन की ओर से देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। …(व्यवधान) आपने गरीब को लाभ दिया है। …(व्यवधान) यही नहीं, छोटे व्यापारी, मध्यम, सूक्ष्म और लघु व्यापारी, एमएसएमई सेक्टर के लिए भी नव वर्ष पर आपने 12 योजनाएं लाकर, इस सेक्टर को आपने एक बहुत बड़ा लाभ दिया है। यह सेक्टर हिन्दुस्तान की इकोनोमी की रीढ़ की हड्डी है। …(व्यवधान) इस वर्ग के लिए एक करोड़ रुपये तक का ऋण मात्र 59 मिनट के अन्दर मिलेगा, यह काम आज तक कोई नहीं कर पाया। …(व्यवधान) इसके लिए इस सरकार ने कदम उठाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। …(व्यवधान) ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया के लिए पहले मात्र 0.02 प्रतिशत ऑप्टिकल फाइबर पहुंची थी, लेकिन मोदी सरकार में इससे 50 प्रतिशत गांव जुड़े हैं और अगले वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ जाएंगे। …(व्यवधान) इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात करें, जो पहले मात्र 2.63 गीगावाट थी, आज यह दस गुना ज्यादा बढ़कर 22 गीगावाट हो गई है। …(व्यवधान) यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2013-14 में एफडीआई 36 बिलियन यूएस डॉलर थी, वह दोगुनी से ज्यादा बढ़कर लगभग 61 बिलियन यूएस डॉलर हुई है। …(व्यवधान) अभी विपक्ष के एक नेता कह रहे थे कि आरबीआई के गवर्नर को हमने मजबूर किया, सदन के सामने असत्य बोलना इनकी आदत बन गई है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दुनिया के देशों में जो डेवेलप्ड इकोनॉमीज हैं, उनका रिजर्व क्या रहता है और जो कंजरवेटिव इकोनॉमीज हैं, उनका रिजर्व फंड कितना रहता है और भारत जैसे देश का रिजर्व फंड कितना रहना चाहिए? आज आप देश को यह बताइए, आज आरबीआई के पास कितना पैसा पड़ा है? जितना पैसा होना चाहिए, क्या उससे ज्यादा पैसा आरबीआई ने अपने पास नहीं रखा है? क्या इससे भारत की इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ रहा है? जो बिल्डिंग अधूरी बनी हैं, सड़कों के निर्माण के लिए पैसा चाहिए, भारत के विकास के लिए पैसा चाहिए, अगर आरबीआई उस पैसे को छोड़ती है तो क्या भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट में उससे इजाफा नहीं आएगा? क्या यह सच्चाई नहीं है कि दुनिया के जो विकसित देश हैं, वहां सात फीसदी रिजर्व रखा जाता है, कंजरवेटिव इकोनॉमीज लगभग 14 फीसदी रिजर्व रखती हैं और अगर भारत जैसे देश में 32 प्रतिशत रिजर्व पड़ा है तो क्या यह भारत के साथ अन्याय नहीं है? अगर यह अन्याय है तो क्या यह अधिकार आरबीआई को है या चुनी हुई सरकार को है कि देश के लोगों के प्रति और देश की अर्थव्यवस्था के प्रति उनको निर्णय करना चाहिए। ये कहते हैं कि रेड आरबीआई पर नहीं, ये आरबीआई की रेड देश की इकोनॉमी पर है। This is not the raid on RBI, this is the RBI's raid on the Indian economy.

मैडम, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है और पिछली यूपीए की भ्रष्ट सरकार थी, जिसमें टू-जी का घोटाला हो, सीडब्ल्यूजी का घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, आकाश से लेकर पताल तक के घोटाले इस पिछली सरकार ने किए। अगस्ता वेस्टलैंड में भी जो बिचौलिया था, अगर आज वह कहता है - मिसेज जी. या वह इटैलियन लेडी की बात करता है। यह इटैलियन लेडी कौन है? मैं यह वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। वह ईडी की गिरफ्त में है। यह कौन इटैलियन लेडी है, जिसका नाम अगस्तावेस्टलैंड में आता है। यह कौन इटैलियन लेडी का बेटा है जिसका नाम उसमें आता है। आखिरकार, भारत के वीआईपीज के लिए जो जहाज खरीदने थे, उसमें भी कौन लोग दलाली खाने में पीछे नहीं रहे, आप यह देश की जनता को बताइए, क्योंकि कॉंग्रेस सदन चलने नहीं देगी, यह सच्चाई सामने नहीं आने देगी।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के मुद्दे पर जब यह कहा कि उन्होंने प्राइस, प्रोसिजर, ऑफसेट क्लॉज सभी को देख कर यह निर्णय दिया है कि किसी को कॉमर्शियल फेवरिज्म नहीं हुआ है तो इसके बाद कुछ नहीं बचता है। दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है और कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। मोदी सरकार ने ईमानदारी के साथ देश के हित में राफेल की खरीद की है। वह बहुत बड़ा निर्णय है। यही नहीं बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि यह देश, जहां हमारी एडवरसरीज ने चौथी और पांचवीं जैनरेशन के एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, India cannot be underprepared and unprepared. …(व्यवधान) मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म कर

रहा हूं। मैं खुद कमीशन ऑफिसर हूं इसलिए कह रहा हूं।...(व्यवधान)क्योंकि दस साल तक कांग्रेस ने लड़ाकू विमान नहीं खरीदे। फौज को कमजारे करने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। पिछले दस वर्षों में ये जानबूझ कर, शायद इनको इटली वाला कोई मामा नहीं मिला होगा, इसलिए ऐसा किया होगा। ...(व्यवधान) पहला क्वात्रोची था।...(व्यवधान) मिसेल मिला और अब उसने भी बोलना शुरू कर दिया, जो उसे बोलना था।

अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहूंगा कि आज यहां इनके नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। आज ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद चेहरा बचाने का प्रयास करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत अंडर प्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड नहीं हो सकता है और यह पूरा देश मानता है कि हमें जो खतरा है, मोदी सरकार भी उस खतरे को जानती है। इसलिए अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भारत हित में जो निर्णय किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की इकोनॉमी और मजबूत हुई है और देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। आपकी योजनाओं के माध्यम से 'सबका साथ-सबका विकास' मूल मंत्र को हासिल किया है और पूरे देश की गरीब जनता का विकास किया गया है। पांच करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए हैं।

हमने दो करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए। ...(व्यवधान) नौ करोड़ बहनों को उज्जवला योजना में एल.पी.जी. सिलेंडर दिए। ...(व्यवधान) 9.5 करोड़ नए शौचालय बनाकर दिए। ...(व्यवधान) 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में पांच लाख रुपये का इलाज मुफ्त में दिया। ...(व्यवधान) 30 करोड़ बैंक खाते खोले। ...(व्यवधान) 22 करोड़ लोगों की इंश्योरेंस करवाई। ...(व्यवधान) यह सब पिछले 70 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई थी। ...(व्यवधान) नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने यह किया है। ...(व्यवधान) आपको इसके लिए बहुत-बहुत बधाई। ...(व्यवधान) मैडम, मैं यह कहूंगा कि :

योजनाओं की सफलता का फैसला जनता की मुस्कान है,

योजनाओं की सफलता का पैमाना जनता की मुस्कान है और

सरकार की सफलता का पैमाना लाभार्थियों की बढ़ती डिमांड है।

आदरणीय वित्त मंत्री जी, आपकी योजना इतनी सफल रही कि आज भारत में 22.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं, जिनको प्रत्यक्ष तौर पर आपकी योजनाओं का लाभ मिला है और इसका वादा आपने देश से किया था। माननीय मोदी जी ने पहले सत्र में कहा था कि मेरी सरकार गरीब की, मज़दूर की, महिला की, नौजवान की, जवान की और किसान की होगी। …(व्यवधान) सभी वर्गों के लिए काम किया है। …(व्यवधान) मैडम, मैं अंतिम यही दो बातें कहूंगा - पूरे होते सारे वादे, मोदी सरकार के मज़बूत इरादे, मोदी सरकार के मज़बूत इरादे। …(व्यवधान) पिछली बार तो हम 282 सीटें जीतकर आए थे। …(व्यवधान) अगली बार 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर आएंगे और देश को जो दुनिया की पहली छह: अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा किया है, अगले पांच वर्ष भी आपको मिलेंगे और दुनिया की पहली तीन अर्थव्यवस्थाओं में हम भारत को लाकर खड़ा करेंगे। …(व्यवधान) आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। …(व्यवधान) मैं एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। …(व्यवधान) आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्रीमती बुत्ता रेणुका।

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Madam Speaker, I would like to put across a few points here.

We have three main sectors in our country – farming sector, weaving sector and business sector. Out of these three sectors, farming is a major sector as 60 per cent of our population is dependent on farming. Almost all our States are demanding that these farmers should be rescued from the loans by waiving their farm loans. Not only that, they are also demanding minimum support price for their crops. *…(Interruptions)* What is happening is that though we are saying that the Government is supporting them with minimum support price, we are unable to implement it in respect of all farmers. Majority of these people, especially in my constituency, grow onion and tomato. Whoever of them has come up with these crops, he is unable to recover even the transportation cost. Due to that, they are forced to throw the crops on the main roads. They are forced to commit suicides. So, if we can think about these things, we can rescue the farmers from committing suicides. So, we have to seriously and sincerely think about this community. *…(Interruptions)*

Another thing is handloom for which GST is a major issue. Due to GST, handloom sector is in a real problem. All these years, there was zero tax. Now, five per cent tax has been imposed on handlooms. As a result, the cost of handloom products has become more than that of a powerloom. For powerlooms, the cost of material is cheaper while the cost of material for handlooms is expensive. *…(Interruptions)* Textiles costing less than Rs. 1,000 attracts five per cent tax while textiles costing more than Rs. 1,000 attracts 12 per cent. So,

the handloom people are really suffering because of this kind of taxation. The handloom people have to form a cluster or a group and then only, they can go for GST. Individually, they are unable to go for GST. So, they are losing the livelihood of doing handloom on their own. Otherwise, all these days, the handloom people, one or two families, were doing it on their own and were also able to sell their product in the market. *…(Interruptions)*

**16 00 hrs**

Due to the GST, they are unable to do this. At the same time, they are unable to go for GST. The GST has become very complicated for those people. They are unable to understand the procedures and formalities and how to go about it. We need to seriously think about this also.

Let me come to the business community. When the small and medium entrepreneurs go for loans, banks straightaway refuse them loans. Due to the financial condition of the banks and due to the bad performance of the banks themselves, they are not implementing even the MUDRA scheme. They are refusing to give loans which they are supposed to give. These are the three sectors on which the Indian economy is completely dependent.

Finally, I would like to mention one thing relating to our State. Our State is a newly formed one. In the AP Reorganisation Act, many things were promised. None of the promises, which were made on the floor of the House, has been implemented. Our State really needs the financial support. I would request the Finance Minister to support the State. There are nearly eighteen to nineteen issues, like the Polavaram project, Vizag Railway Zone, Kadapa Steel factory, which need to be seriously looked into by the Central Government and help the Government of Andhra Pradesh by extending the financial support. Thank you.

**श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) :** अध्यक्ष महोदया, मैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। 84 हजार करोड़ रुपये की डिमांड्स में से 30 हजार करोड़ रुपये कैश मांगा गया है। मैं समझता हूं कि सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब और हेल्थ की है और उसको पूरा करने के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत है। हेल्थ का टारगेट ढाई परसेंट का रखा गया, लेकिन वह जीडीपी का 1.1 परसेंट है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर माननीय वित्त मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। रिसर्च के लिए जीडीपी का आधा परसेंट रखा गया है। रिसर्च के बिना काम नहीं चलता है। हम सोइल हेल्थ कार्ड लेकर आए, लेकिन हमारे पास लेबोरेट्री नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए और पैसा रखा जाना चाहिए। हमारे यहां इंडस्ट्री की और बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन मैं कृषि की बात करना चाहता हूं क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा आबादी इस पर निर्भर है। हमें यह सोचना होगा कि जब देश आजाद हुआ तो एग्रीकल्चर प्रोफिट में थी तो आज लॉस में क्यों है? उस समय स्लोगन था – उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखद चाकरी। लेकिन आज कृषि को निखद क्यों माना जाता है? इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्होंने ज्यादा समय राज किया, ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है। आज की सरकार को लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है, उसको चैलेंज के रूप में लेना होगा। मेरे कुछ सुझाव वित्त मंत्री जी के लिए हैं कि कृषि को इंडस्ट्री पर डिपेंड करने की क्या जरूरत है? कृषि के लॉस में जाने का बड़ा कारण यह है कि यह इंडस्ट्री पर डिपेंड हो गयी। कृषि के नाम पर इंडस्ट्रियलिस्ट मालामाल हो गए, जबकि किसान खुदकुशी करता चला गया, क्योंकि वह भूखा मर रहा है। इसके लिए कृषि को आत्मनिर्भर करने की पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। कोई विशाल एग्रीकल्चर पॉलिसी बने जिससे कृषि को लॉस से निकाला जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा लेकर आए, भले ही किसान से कम पैसे लिए जाते हैं, मगर सरकार तो दे रही है। फसल बीमा योजना के नाम पर कम्पनियों ने करोड़ों रुपये बना लिए और किसानों को कुछ नहीं मिला है। मेरा कहना है कि इसके लिए एक कॉर्पोरेशन बनना चाहिए ताकि जो प्रोफिट है, वह किसान के हित में जाना चाहिए। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में किसान को कर्ज मुक्त करना होगा। इसके लिए वन टाइम सेटलमेंट प्लान बनाया जाए या रेट ऑफ इंटरेस्ट वेव-ऑफ किया जाए। कम से कम किसान के लिए पेंशन स्कीम तो लायी जानी चाहिए। बाकी सभी को पेंशन मिलती है, लेकिन किसान को पेंशन नहीं मिलती है। दूसरा, डीजल-पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। मैं चाहता हूं कि इसको जीएसटी में ले लिया जाना चाहिए। ईंधन के साधनों को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोगों को बहुत नुकसान होगा।

अंत में मैं पंजाब की कुछ बात बताना चाहता हूं। मैडम, आज अनन्तकुमार जी हमारे बीच में नहीं रहे। जब तक वह रहे थे, तब तक यूरिया का एक भी थैला भी ब्लैक नहीं गया, कभी कोई कमी नहीं आई, लेकिन आज कमी आने लगी है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी संसदीय क्षेत्र में एक एन.एफ.एल. का कारखाना है। केवल 1,100 करोड़ रुपये की जरूरत है। सारा इन्फ्रास्ट्रैक्चर बना हुआ है, बिल्डिंग भी है, पानी भी है, गैस भी

है और जमीन भी है। अगर आप उसको शुरू करवा दें, तो अच्छा रहेगा। यह ध्यान देने की बात है और मैं हर बार कहता हूं कि 1,100 करोड़ रुपये में एन.एफ.एल. का कारखाना चल सकता है। आज यूरिया की कमी है।

दूसरी, एक सावन नदी हिमाचल से आती है। अब मेरे संसदीय क्षेत्र में आने से नुकसान होता है। आपने हिल एरिया को स्पेशिल इन्सेंटिव दिए हुए हैं। मगर जो कंडी एरिया है, वह उस किस्म की प्राब्लम फेस करता है। कम से कम कंडी एरिया को तो हिल एरिया जैसी फैसेलिटी दी जानी चाहिए।

तीसरा, पंजाब सरहदों वाला क्षेत्र है, यह हम हर बार कहते हैं। पंजाब ने पहले मिलिटेन्सी को झेला। कम से कम पंजाब के लिए कुछ न कुछ पैकेज दिया जाए। मैडम, सारा देश कहता है और सभी माननीय सांसद भी कहते हैं कि जंगली जानवरों से जानी और माली नुकसान होता है। किसान 50 प्रतिशत शेयर देने को तैयार है, 25 प्रतिशत आप कर लीजिए और 25 प्रतिशत राज्य सरकार दे दें, तो जालीदार लगा लें। किसान सुखी हो सकता है। कुछ ऐसी ही सिंचाई की बात है। 11 मिलियन मिट्रिक पानी हमारा है। उसमें से हम केवल 6 मिलियन मीट्रिक पानी का इस्तेमाल

करते हैं। कम से कम जो 5 मिलियन मीट्रिक पानी है, उसके लिए कोई उपाय किया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र में पठानकोट से लेकर मोहाली तक अगर चेक डैम लग जाए, तो मैं समझता हूं कि पंजाब और हरियाणा के पानी पूरा किया जा सकता है। रेन वाटर को भी बचाया जाए। ऐसा मेरा सुझाव है।

**श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब जी ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान की पूरक मांग पेश की है। मैं इस पर अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज 31 दिसम्बर आ गया है। नया साल आ जाएगा, सभी माननीय सदस्यों को नए वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, वहीं यह साल आपके लिए अंतिम साल साबित हो रहा है। यह फिर लौट के नहीं आएगा। उसके कारण हैं कि अर्थव्यवस्था की आपने चेन

पुलिंग कर दी है। अर्थव्यवस्था की गाड़ी की चेन पुलिंग करके रोक दी गई है, जिससे देश की कमर टूट गई है। देश का आवाम, देश का नौजवान और देश का किसान, चारों तरफ तबाही का मंजर है। तारों तरफ त्राहिमाम-त्राहिमाम है। आर्थिक स्थिति बहुत ही बदहाल है। जैसे मुंबई के शेयर मार्केट में उछाल आता है, तो खूब चर्चा होती है। लेकिन पांच साल आते-आते भारतीय जनता पार्टी और आपकी हुकुमत का शेयर मार्केट में बाजार भाव लुढ़क गया है। ऐसा लुढ़क गया है कि अगर आप लाख कोशिशों के बाद भी बनाना चाहेंगे, तो वह सुधरने वाला नहीं है। आपका शेयर मार्केट घट गया है। आज की तारीख में जो आपने वचनबद्धता जाहिर की है, यह हम नहीं कह रहे हैं, विपक्ष नहीं कह रहा है, देश का नौजवान किसान नहीं कह रहा है। आपने जो देश के सामने वचनबद्धता जाहिर की थी - वादा तेरा वादा, तेरे वादे पर मारा गया जनता सीधा-साधा, लेकिन उसका हित नहीं किया।

अध्यक्ष महोदया, दो मिनट का समय दीजिए। मैं आपसे निवेदन करके ले रहा हूं और इसीलिए वादे पर बोल रहा हूं। मुझे बोलने का आप ही हक दीजिएगा। हम लोगों ने शुरू में कहा था कि उद्योगपतियों को नोटबंदी में माफ किया और गरीबों को साफ किया। नोटबंदी हुई, गंगा की सफाई होते-होते, इसी पर पैसा ले रहे हैं। एयर इंडिया पर ले रहे हैं। गंगा की सफाई तो नहीं हुई, लेकिन दिन-दहाड़े नीरव मोदी बैंक साफ करकर चला गया। यह इस देश की हकीकत है। यही इस देश की सच्चाई है। स्विस बैंक में काला धन है, अब कहा जाता है कि स्विस बैंक का स्विच ऑफ हो गया है। ऑन करने पर ऑन नहीं होता है। वर्ष 2019 में आपका भी स्विच ऑफ हो जाएगा, ऑन होना वाला नहीं है।

एक मिनट समय दीजिए ना, हम कोई गलत थोड़े ही बोल रहे हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** सवाल गलत का नहीं है। सवाल समय का है।

**श्री जय प्रकाश नारायण यादव :** आप ही की कृपा से बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदया, इस देश को बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गाँव चाहिए। किसान को सहूलियत चाहिए।...(व्यवधान) आज की तारीख में बुलेट ट्रेन पर आप सवारी कीजिए। वर्ष 2018 की 21 तारीख तक बुलेट ट्रेन पर आप चढ़िये, जनता पायलट ट्रेन पर चढ़कर 2019 में विदाई करेगी।...(व्यवधान) इसलिए अध्यक्ष महोदया, 15 लाख का क्या हुआ? दो करोड़ नौजवानों की नौकरी का क्या हुआ? नौकरी माँगते हैं तो कहते हैं कि पकोड़े की दुकान खोलिए।...(व्यवधान) अब 2019 में आप पकोड़े की दुकान खोलिएगा। यह आपका होगा, यह मेरा नहीं होगा। राफेल डील का, जनधन योजना का, डिजिटल इंडिया का, जीएसटी का, आरबीआई का, आयुष्मान भारत का, कहावत है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा लोभ से

फँसाएगा, अब कोई आपके लोभ में फँसने वाला नहीं हूँ...(व्यवधान) वे तो हमारे मित्र हैं, इसलिए आज की तारीख में बिहार में दुष्कर्म, हत्या, डकैती, बलात्कार...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** हो गया।

**श्री जय प्रकाश नारायण यादव :** लूट हो रही है। इसलिए न सरहद की सुरक्षा, न सड़क की सुरक्षा, न बैंक की सुरक्षा, सिर्फ सपने परोसने का काम हुआ।...(व्यवधान) कैशलैस-कैशलैस, बेसलैस-बेसलैस। यह तो होपलैस-होपलैस।

**माननीय अध्यक्ष :** हो गया।

**श्री जय प्रकाश नारायण यादव :** यही तो है। अध्यक्ष महोदया, आपने समय दिया, दो मिनट और कहने का मौका दिया।...(व्यवधान) यह लगभग अंतिम बजट ही है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।

**श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार):** धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया। मंत्री जी की ओर से लगभग 86 हजार करोड़ की सप्लीमेंट्री कैपिटल और रेवेन्यू को मिलाकर पेश की गई है।...(व्यवधान) मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि हेल्थ इस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और मंत्री जी ने जिस प्रकार से 50 करोड़ लोगों के लिए एक नेशनल स्कीम बनाई है।...(व्यवधान) मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अधिकतम सरकारी अस्पताल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसे हैं, जहाँ एमआरआई, सीटी स्केन जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है।...(व्यवधान) आज वहाँ से पेशंट को उठाकर हमें मेडिकल कॉलेजेज में भेजना पड़ता है। क्या स्कीम के साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं या केवलमात्र पेशंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रेफर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतम जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस देश के अंदर हैं, वे फॉरेन कम्पनीज द्वारा एक्वायर किए जा रहे हैं।...(व्यवधान) यह आने वाले समय में हमारा जो टेलेंट है, जो हमारे छोटे-छोटे अस्पताल शहरी क्षेत्र में हैं, उनको खत्म करने का भी प्रयास है।...(व्यवधान) आप ज़रूर अगर ऐसी अच्छी स्कीम लेकर आते हैं तो जो बेसिक सिविल हॉस्पिटल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करिए। मेरी लोक सभा के अंदर आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हिसार में सिविल हॉस्पिटल है उसकी यह हालत है कि वहाँ पर मॉर्चरी में भी पोस्टमार्टम करने के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है।...(व्यवधान) एक सिविल सर्जन

को आकर ऐसी फैसिलिटी को ओवरलुक करना पड़ता है। वहाँ पर आज एमआरआई, सीटी स्केन नहीं है। डॉक्टर रेफर करते हैं और पेशंट को कहीं बाहर जाकर यह जाँच कराकर आना पड़ता है।...(व्यवधान)

आपके बजट का एक जो हिस्सा था, मैं रिवर की बात करता हूँ। हमारे ओडिशा के साथी, कर्नाटक के साथी भी इस बारे में बारी-बारी कहते हैं।...(व्यवधान) इंटरलिंकेज ऑफ रिवर एक बहुत बड़ी बात अटल जी ने कही थी और उससे पहले चौ. देवीलाल जी के समय में एक बात शुरू की गई थी कि यमुना के ऊपर डैम बनाए जाएँगे।...(व्यवधान) पिछले बजट में 1800 करोड़ रुपये रेनुका डैम के लिए आपने मंजूर किए थे।...(व्यवधान) पर आज तक उसके ऊपर काम नहीं शुरू हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार उसमें एडिशनल फंड्स देकर जल्द से जल्द वह सपोर्ट करे कि एटलीस्ट जो वाटर क्राइसेस है, जैसे चंदूमाजरा जी मेरे से पहले कह रहे थे कि चैक डैम्स बनाइए, पानी की कमी जो हरियाणा प्रदेश में है, वह डार्क जॉन में जा रहा है, कहीं न कहीं उसके अंदर मदद कर पाएँगे अगर रेनुका, लखवार और किशाऊ तीनों डैम बन पाएँगे।

**माननीय अध्यक्ष :** ठीक है। हो गया।

**श्री दुष्यंत चौटाला :** एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कर्मचारी फेस कर रहे हैं, वह न्यू पेंशन स्कीम की है। वर्ष 2004 के बाद और कई प्रदेशों में वर्ष 2006 के बाद यह देखा जा रहा है कि स्टॉक मार्किट में उनकी पेंशन को इनवेस्ट कर दिया जाता है। जुलाई और दिसम्बर दो महीने तय कर दिए गए कि जब वे फंड्स डेवलप होंगे। आज यह हालत है कि फाइनेंशियल क्राइसेस का किसी को नहीं पता है। कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन व्यतीत करकर रिटायर होता है और उस टाइम पर अगर फाइनेंशियल मार्किट में डाउनफॉल आए तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसके भविष्य को भी असुरक्षा मिलती है।

यह सरकार इस पर वर्क जरूर करे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को किसी न किसी तरीके से इस देश में रिवाइव किया जाये। मैं किसान के कर्ज की बात करना चाहता हूँ। आज किसान के कर्जे की बात कांग्रेस कर रही है। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि चौधरी देवी लाल जी ने जब किसान के कर्जे की बात कही थी तो पैन इंडिया दस हजार रुपये तक का कर्जा माफ करने की बात की थी। आज इस चीज की जरूरत है। हम एक राज्य में दो लाख रुपये का कैप करते हैं, दूसरे राज्य में तीन लाख का कैप करते हैं, कहीं न कहीं हम किसान में भी भेदभाव कर रहे हैं। अगर किसानों का कर्ज माफ करना है तो मोदी सरकार को केन्द्र लेवल पर इस पॉलिसी को लाना पड़ेगा। कम से कम सहकारी बैंकों का जो कर्ज किसानों के ऊपर है, मैं प्राइवेट बैंकों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन किसानों के ऊपर जो कोआपरेटिव बैंक्स का कर्ज है, क्योंकि वह आपका हिस्सा है, कम से कम उस लोन को वेव करने के लिए किसी प्रकार की पॉलिसी बनाने का आप काम कीजिए।

मैं अंत में एक चीज कहना चाहूँगा क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री ने निरन्तर कहा है कि हम हायर एजुकेशन को आगे लेकर जाने का काम करेंगे। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हायर एजुकेशन तो तब पूरी होगी जब लोअर एजुकेशन इम्प्रूव कर पाएंगे। आज जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कम्प्यूटर लैब्स नहीं हैं। आज हम बच्चे को कम्प्यूटर छूना भी 8वीं, 9वीं कक्षा में लाकर, सीनियर और सीनियर सेकेण्डरी में सिखाने का काम करते हैं। अगर हमें डिजिटल इंडिया बनाना है तो कम से कम स्कूल लेवल पर जाकर हमें डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा और प्राइमरी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की जाएगी।

महोदया, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि आपके प्रदेश में अतिथि अध्यापक हैं, हमारे प्रदेश में गेस्ट टीचर्स हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्र हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस देश के अंदर जहाँ हम शिक्षा को आगे ले जाने की बात करते हैं, हमारे अध्यापकों को हम गेस्ट बनाकर रखते हैं। सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगर किसी भी टेम्परेरी कर्मचारी को अगर गवर्नमेंट सेक्टर में 8-10 साल काम करते हुए हो गए हों तो उन्हें हम कैजुअली भर्ती करें और उनको रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत लाने का काम करें। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ रहे हैं, आज लाखों ऐसे कर्मचारी हैं, लगभग दो लाख के आसपास तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में टीचर्स हैं, जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशानुसार बेरोजगार होना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि सरकार इस बजट के साथ-साथ इस पर जरूर विचार करे कि कैसे हम उन टेम्परेरी कर्मचारियों को रेगुलराइज करने का काम करें। अंत में मैं खेलों के बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि 2020 का ओलम्पिक पोडियम का टारगेट है। सरकार काम कर रही है, बृजभूषण शरण सिंह मेरे साथ रेसलिंग फेडरेशन में हैं, हम देखते आ रहे हैं कि सरकार स्पोर्ट्समैन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बात करती है। जब तक आप गाँव स्तर पर नर्सरी डेवलप नहीं करेंगे तब तक हिन्दुस्तान विदेशों से कम्पीट नहीं कर पाएगा। आज हम अमेरिका, यू.के. की बात करते हैं।

आप उनकी नर्सरीज को जाकर देखने का काम करिए। हम पैसा टॉप्स को दे रहे हैं, हम उन खिलाड़ियों को पैसा दे रहे हैं जो कहीं 'खेलो इंडिया' में खेल रहा है। हमें उस खिलाड़ी पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आने वाले भविष्य में इस देश का खिलाड़ी बनेगा। मैं आग्रह करूँगा कि आप स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाकर स्पोर्ट्स के विस्तार के लिए जैसे पहले युवा खेल क्रीडा योजना होती थी, उस प्रकार से अगर कोई ग्राम पंचायत 5-6 एकड़ जमीन दान देकर अपने ग्राम में स्टेडियम बनाने का काम करे तो केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ 1.5-2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके या स्टेडियम बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो, आप वह इन्वेस्ट कीजिए। आप उसके बाद रिजल्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश आज 30 परसेंट मेडल टेली का हिस्सा लाता है और फिर हमारा देश इसी तरीके से

ओलम्पिक में 30 परसेंट मेडल टेली का हिस्सा लाने का काम करेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली):** महोदया, सप्लीमेन्टरी ग्रांट्स देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त करने का एक अवसर होता है।…(व्यवधान) कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं।…(व्यवधान) मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।…(व्यवधान) वैसे तो सप्लीमेन्टरी ग्रांट्स एक एडिशन 85 हजार करोड़ की हैं, लेकिन उसमें से लगभग 70 हजार करोड़ टेक्निकल ग्रांट्स हैं और 15 हजार करोड़ रुपये का एक एडिशनल एक्सपेंडिचर है।…(व्यवधान) जिसके ऊपर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं।…(व्यवधान) जिन 4-5 विषयों पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, मैं उन पर संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी दे देता हूँ।…(व्यवधान)

माननीय सौगत राय जी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की चिंता सबको है।…(व्यवधान) चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन इसलिए इतनी चिंता न करें कि कांग्रेस के या और किसी दल के शासन में इस देश को कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था कि वह दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो।…(व्यवधान) यह केवल नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, जिसमें इस देश को 5 साल तक यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है।…(व्यवधान)

जब कांग्रेस की सरकार गयी थी तो याद करें कि यूपीए-II में क्या स्थिति थी।…(व्यवधान) अगर हम यूपीए-II के पाँच साल ले लें तो उस समय इंफ्लेशन कितनी थी? वह 10.4 प्रतिशत थी।…(व्यवधान) 10.4 पर्सेंट मुद्रा स्फीति यूपीए-II के दौरान थी, जो आज साढ़े तीन पर्सेंट से नीचे औसतन आई है।…(व्यवधान) आज की तारीख में तो यह केवल 2.3 प्रतिशत है।…(व्यवधान)

हमारा जो फिस्कल डिसीप्लीन रहा, उसके बारे में मैं यक़ीनन यह कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद से जितनी सरकारें आई हैं, इंफ्लेशन को कंट्रोल करना, फिस्कल डेफिसिट को नीचे लाना, करेन्ट एकाउंट डेफिसिट को नियंत्रण में रखना, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स को बनाए रखना और अर्थव्यवस्था को स्थिरता और स्टैब्लिटी देना, ऐसा कोई उदाहरण इतिहास के अन्दर आपको दुबारा नहीं मिलेगा।…(व्यवधान) इस सरकार ने पहली बार इस उदाहरण को कायम किया है।…(व्यवधान)

महोदय, यह स्वाभाविक है कि इसमें चुनौतियां भी हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोग उस अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने का एक प्रयास करते हैं।...(व्यवधान) बार-बार यह सवाल आता है कि डिमॉनेटाइजेशन, जी.एस.टी. का क्या लाभ हुआ? ...(व्यवधान) मैं केवल दो-तीन विषय इस पर रख दूं।...(व्यवधान) अभी अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे।...(व्यवधान) अनुराग ठाकुर जी यह बता रहे थे कि इस देश के गरीबों के साथ क्या-क्या हुआ।...(व्यवधान) अगर हम गांवों से शुरू करें तो हर गांव को पक्की सड़क के साथ जोड़ देना और जो कांग्रेस सरकार के दौरान रकम दी जाती थी, उसको तीन गुना बढ़ा देना, यह काम नरेन्द्र मोदी की सरकार ने किया है।...(व्यवधान) ये साधन कहां से आएंगे? वर्ष 2022 तक गांवों में रहने वाले हर गरीब के पास पक्के मकान होंगे।...(व्यवधान) कांग्रेस के जमाने में जो सात-आठ लाख मकान प्रति वर्ष बनते थे, वहीं अब 45 लाख मकान प्रति वर्ष बन रहे हैं, क्योंकि अगले साल तक एक करोड़ मकान बनाने की योजना है।...(व्यवधान) गांवों में गरीबों के लिए ये मकान बनाने हैं।...(व्यवधान) इसका खर्च कहां से आएगा? ...(व्यवधान)

अभी अनुराग जी ने सैनिटेशन का जिक्र किया।...(व्यवधान) 02 अक्टूबर, 2014 में गांवों में 39 प्रतिशत घर ऐसे थे, जहां शौचालय था।...(व्यवधान) 30 नवम्बर, 2018 को वे 97 प्रतिशत हो चुके थे।...(व्यवधान) आज केवल तीन प्रतिशत ऐसे घर बचे हैं, जहां शौचालय नहीं है।...(व्यवधान) एक गांव ऐसा नहीं बचा, जहां बिजली न हो।...(व्यवधान) आज 31 दिसम्बर, 2018 हर राज्य के लिए अन्तिम दिन था कि वे चार करोड़ गरीब लोग, जिनके घरों में बिजली नहीं थी, चाहे उनके गांवों में आ गयी थी, उनके घरों तक बिजली को देना, यह प्रयास इस सरकार ने किया।...(व्यवधान) आठ करोड़ गरीब परिवारों को गैस का चूल्हा देना, जिसमें से लगभग छः करोड़ परिवारों को दिया जा चुका है।...(व्यवधान)

अभी हमारे मित्र चौटाला जी 'आयुष्मान भारत' का जिक्र कर रहे थे।...(व्यवधान) कल 'आयुष्मान भारत' को 100 दिन पूरे होंगे।...(व्यवधान) 100 दिनों में लगभग सात लाख लोग अस्पतालों में मुफ्त में इलाज़ करा चुके हैं।...(व्यवधान) मैं यह मानता हूं कि दूसरे और तीसरे वर्ष के दौरान इस देश के लगभग एक करोड़ गरीब लोगों का हर साल हॉस्पीटल ट्रीटमेंट इस देश में मुफ्त कराया जाएगा।...(व्यवधान) इतनी बड़ी सरकारी हेल्थ केयर योजना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है।...(व्यवधान) उसमें जो 16,500 अस्पताल रजिस्टर हुए हैं, इनमें सरकारी अस्पताल भी हैं और प्राइवेट अस्पताल भी हैं।...(व्यवधान) इसी के पैसे के आधार पर जब अस्पतालों को पेमेंट जाएगी तो एक प्रकार से नयी टेक्नोलॉजी को लाने की उनकी क्षमता स्वाभाविक रूप से अपने आप बढ़ेगी।...(व्यवधान) इसके साथ-साथ हम देख लें कि यह पैसा कहां से आया?...(व्यवधान) जब इस देश में जी.एस.टी. नहीं था, डिमॉनेटाइजेशन नहीं हुआ था तो इनकम टैक्स देने वाले लोग जो रिटर्न फाइल करते थे, वे 3.8 करोड़ लोग थे।...(व्यवधान) कांग्रेस के समय ऐसे 3.8 करोड़ लोग थे, यानी जब से इनकम टैक्स एक्ट आया, केवल 3.8 करोड़ लोग

ही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते थे।...(व्यवधान) हमारी सरकार के पहले चार वर्षों में यह 6.86 करोड़ हो गया और जब पाँच साल पूरे होंगे तो वह 3.8 करोड़ लोगों का आंकड़ा लगभग दोगुना हो चुका होगा।...(व्यवधान)

किसी सरकार ने रिटर्न फाइल करने वालों के इनकम टैक्स का आंकड़ा दोगुना नहीं किया।...(व्यवधान) जीएसटी के पहले 18 महीनों में ही 74 परसेंट असेसीज़ बढ़ गए।...(व्यवधान) 1200 में से 500 आइटम पर टैक्स नहीं लगता है। 700 आइटम पर टैक्स लगता है और अभी 360 आइटम पर टैक्स घटा दिया गया। यह उपभोक्ता के पक्ष में है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आप कोई उदाहरण बता दीजिए, शायद आप इस संसद में सबसे अनुभवी लोगों में से हैं, आपने भी संसदीय जीवन में जो देखा होगा, किसी भी बजट में एक परसेंट इनकम टैक्स नहीं बढ़ा, बल्कि हर बजट में रियायत दी गई।...(व्यवधान) हमने जीएसटी में हर टैक्स के अंदर रियायत देने की कोशिश की। टैक्स का बेस बनाकर कलेक्शन इतना बड़ा कर दिया और डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से जो लोग चोरी करते थे, अब वे व्यवस्था में आए हैं।...(व्यवधान) आयुष्मान भारत, गांव की सड़क, शौचालय की व्यवस्था, बिजली, घर, गैस का चूल्हा उसी पैसा से आया है, जो पहले इनके राज्य के दौरान चोरी में जाता था।...(व्यवधान) आज वह पैसा नरेन्द्र मोदी के शासन के दौरान गरीबों के घर तक पहुंचता हैं और गरीब की जेब में पहुंचता है।...(व्यवधान) फर्क इतना है कि कांग्रेस ने सिर्फ नारे दिए थे, लेकिन नरेन्द्र मोदी ने उनको साधन दिए हैं।...(व्यवधान) व्यक्ति की गरीबी साधनों से जाती है, केवल नारों से नहीं जाती है।

मैं आपको इतना भी बतला दूं, अभी सौगात राय जी ने कहा कि आज बैंकों की क्या स्थिति है।...(व्यवधान) वर्ष 2008 में बैंकों ने कुल मिलाकर 18 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया था, वर्ष 2014 में जब यूपीए की सरकार गई, तो यह 18 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 55 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।...(व्यवधान) एक-एक साल में 31 परसेंट ग्रोथ कर देना, आप ऐसा इन-डिसक्रिमिनेट ग्रोथ करेंगे, जिस उद्योगपति को पैसा देंगे, लेकिन उनसे वसूली नहीं होगी।...(व्यवधान) जब वसूली नहीं होगी, तो बैंक आगे कैसे काम करेगा।...(व्यवधान) इन्होंने देश के साथ दूसरा धोखा दिया, किताबों में दिखा दिया कि ढ़ाई लाख करोड़ रुपये का एन.पी.ए. है।...(व्यवधान) जब रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 में एसेट कॉल का रिव्यू किया, तो उनको पता चला कि यह ढाई लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा झूठा है।...(व्यवधान) यह तो साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये है। उस साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये को वापिस लाने के लिए यह सरकार इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेकर आई।...(व्यवधान) उसके बाद एक झूठा प्रचार शुरू कर दिया गया।...(व्यवधान) जो सौ झूठ बोलते हैं कि पन्द्रह लोगों का ढाई लाख करोड़ रुपये माफ कर दिया गया, आपने उन पन्द्रह लोगों के लिए ढाई लाख करोड़ रुपये उड़ा दिया था।...(व्यवधान) बैंकों को लूटकर उनको दे दिया था। नरेन्द्र मोदी ने उनको कंपनियों से बाहर कर दिया, उनकी कंपनियां जब्त कर ली गईं

और आज वह पैसा बैंकिंग व्यवस्था के अंदर वापस आ रहा है।…(व्यवधान) आईबीसी आने के बाद अलग-अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से लगभग तीन लाख करोड़ रुपये वापिस आ चुका है और उससे बैंक की बैंलेंसशीट बदलने लगी है।…(व्यवधान) इसके साथ-साथ बैंकों की ऋण देने की क्षमता भी बढ़ी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बैंक का री-कैपिटलाइजेशन हो,…(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, देखिए, सच बड़ा कड़वा होता है। इस सच को सुनने के बजाय खड़गे जी भी नारे लगाने लगे हैं।…(व्यवधान) खड़गे जी, बहस का जवाब बहस से दीजिए, नारे और झूठ से कुछ नहीं होता।…(व्यवधान)

आप लोगों ने एक जिक्र किया कि जीडीपी का स्लो-डाउन हुआ है। जीडीपी का स्लो-डाउन वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2014 तक हुआ, जब चार परसेंट प्लस तथा पांच परसेंट प्लस तक जीडीपी आ गई थी।…(व्यवधान) आज जीडीपी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली है। दुनिया की ग्रोथ रेट तीन परसेंट है, लेकिन हमारी ग्रोथ साढ़े सात परसेंट है।…(व्यवधान) आज हम चाइना से भी अपने ग्रोथ रेट में लगभग एक परसेंट आगे है। जब इतना फर्क आ चुका है, तो पता नहीं सौगत राय जी किस युग की बात करते हैं।…(व्यवधान) उन्होंने कहा कि आप लोग बैक सीरिज लेकर आएं हैं, मैं बताना चाहता हूं कि बैक सीरिज का एक आर्थिक डाटा होता है।…(व्यवधान) यह आठवीं बार है, जब सी.एस.ओ. की बात आई है, इससे नीति आयोग का कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि सेन्ट्रल स्टेस्टिकल ऑर्गनाइजेशन का संबंध होता है।…(व्यवधान) जब आठवीं बार बैक सीरिज की बात आई, डेटा रिवाइज करना, बेस ईयर को बदलना और अब बैक सीरिज बनाने की एक्सरसाइज हो रही है। सी.एस.ओ. बहुत ही विश्वसनीयता वाला संस्था है।…(व्यवधान) जब सी.एस.ओ. का बैक सीरिज शुरू हुआ, तो यूपीए के आखिरी दो साल का ग्रोथ बढ़ गई।…(व्यवधान) जब यह बढ़ी, तो चिदम्बरम साहब ने बयान दे दिया कि यह तो बहुत अच्छा हुआ, इससे तो हमें सर्टिफिकेट मिल गया।

जब पहले 8 वर्षों की ग्रोथ कम हो गई, तो उन्होंने कहा यह बिल्कुल झूठा है और फर्जी है। यह एक रिवाइज्ड डेटा है। यह पूरी दुनिया की परम्परा है, आधुनिक तरीकों के एकदम अनुकूल है। …(व्यवधान)

एक विषय उठाया गया कि आप आरबीआई के रिजर्व्स लेना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, मैं बता दूं कि फिसकल डेफिसिट को संभालने में जो इस सरकार का ट्रैक रिकार्ड है, आज तक किसी सरकार का नहीं रहा। फिसकल डेफिसिट के लिए मुझे आरबीआई के रिजर्व्स नहीं चाहिए। प्रश्न केवल इतना है कि पहले तीन बार एक्सपर्ट कमेटीज वर्ष 1997, 2004 में और 2013 में बैठ चुकी हैं कि आरबीआई के रिजर्व्स कितने होने चाहिए। आज विषय है कि इकोनामिक कैपिटल फ्रेमवर्क आरबीआई को कितना चाहिए। विश्व के कई देश हैं, जिनको एसेट्स का 8 पर्सेंट है, जो कंजर्वेटिव देश हैं, उनको 14 पर्सेंट है, क्या भारत में 27-28 पर्सेंट चाहिए? यह वह पैसा है, जो बैंक के

रीकैपिटलाइजेशन में जा सकता है। यह वह पैसा है, जो गरीब की गरीबी को दूर करने में जा सकता है। इसके लिए एक कमेटी बने और कमेटी का फैसला जब उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे, उसके कंपोजीशन का फैसला तभी हो चुका था, जिसकी घोषणा अब की गई है। सरकार चाहती है कि इसका नीतिगत निर्णय, कुछ विशेषज्ञों की सलाह और मदद के साथ हो जाए, ताकि हम लोग उसको क्रियान्वित कर पाएं।

अंत में, मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसान को एमएसपी मिले। उसका पहला प्रयास उसे डेढ़ गुना ज्यादा मिले, खर्च के बाद से 50 पर्सेंट ज्यादा मिले, यह प्रयास इस सरकार ने किया है। किसान के सम्बन्ध में उसकी तकलीफ हटे, जितने भी कदम उठाने होंगे, यह सरकार अंतिम कदम तक उठाएगी, यह मैं सदन के सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को यह सदन अपनी स्वीकृति दे।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants – Second Batch for 2018-19 to the Vote of the House.

The question is:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2019, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 5, 8, 9, 11, 13 to 18, 20, 23 to 36, 41, 42, 44, 46 to 48, 52 to 54, 56 to 61, 64 to 68, 70, 72 to 74, 78, 80 to 82, 84 and 87 to 99."

*The motion was adopted.*

**श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा):** माननीय अध्यक्ष महोदया, इस देश में जो दो-तीन चीजें हुई हैं, बैंकों की जो स्थिति खराब है, उसका कारण यह है कि बासिल नार्म्स, जो एक प्राइवेट बॉडी है, उसे भारत सरकार ने यूपीए के कारण इंप्लीमेंट किया। बासिल प्लस, प्लस चल रहा है, जिसके कारण बैंक के एनपीए बढ़ रहे हैं। …(व्यवधान)

दूसरा, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम का भारत पार्ट हो गया है, वह भी एक प्राइवेट बॉडी है और जो सिगनेटरी कंट्रीज हैं, वे लोग भी अपने यहां लागू नहीं कर रहे हैं। उन दोनों के बारे में भारत सरकार क्या सोचती है? …(व्यवधान)

तीसरा, एक किताब आई, टर्नर एक बड़े इकोनामिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि बिटवीन डेट एंड द डेविल, उसमें जो अमेरिका की इकोनामी है, जापान की इकोनामी है, चाइना की इकोनामी है, वह फिसकल डेफिसिट को बहुत नहीं मानती है और वह विकास के लिए जीरो बजटिंग को मानती है। भारत सरकार की, आरबीआई की जो लड़ाई चलती है, जो सरकार का साथ नहीं देती है, उसके बारे में भारत सरकार क्या सोचती है? …(व्यवधान)

**वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली):** महोदया, बैंक के संबंध में क्या नार्म्स हों यह आरबीआई की पॉलिसी है, उन्होंने बैसल-III नार्म्स अधिक रखा हुआ है। इस विषय को सरकार ने उठाया है और यह आरबीआई बोर्ड में विचाराधीन है। …(व्यवधान) जहां तक फिसकल डेफिसिट का प्रश्न है। हम लोग मानते हैं कि फिसकल डेफिसिट जैसी परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था है। आज की तारीख में भारत के लिए डिसिप्लन्ड इकोनॉमी होना आवश्यक है। …(व्यवधान) इस ओर भारत सरकर का पूरा ध्यान और प्राथमिकता है।